सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./ दुर्ग /94/2020-22

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 14 अंक - 279 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, शनिवार 22 जुलाई 2023 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास - खबर

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में जमकर बरसेंगे बादल

भिलाई। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर संभाग के रायगढ़, जांजगीर और उससे लगे जिलों में एक दो जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी बस्तर संभाग के भी कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा सरगुजा संभाग के कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है।

अब तक छत्तीसगढ़ के भोपालपट्टनम -8 सेमी, माकड़ी, बिलासपुर 7 सेमी, बीजापुर, दुर्ग 6 सेमी, फरसगांव,केशकाल, भैरमगढ़, कटेकल्याण, कोडागांव, डोंडीलोहारा, डोंगरगढ़ -5 सेमी, नरहरपुर, बकावंड गुंडरदेही, चरामा, नारायणपुर,पाली, देवभोग, धमतरी, मानपुर, सुकमा, जगदलपुर, कुआकोंडा, बालोद, मोहला, उसूर डोंगरगांव, बस्तर, नगरी, कांकेर, दुर्गकोंदल, गुरुर, पखांजुर, राजनांदगांव, बडेराजपुर, कोटा, खैरागढ़, पथरिया, कुरूद, लोहांडीगुडा -2 सेमी, मगरलोड,भानुप्रतापपुर, आरंग, बास्तानार, कोरबा, अकलतरा, गीदम, पाटन, गरियाबंद, छुरा, माना-रायपुर-एपी, दंतेवाड़ा, ओरछा 1 सेमी बारिश हुई।

अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एक कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण तटीय ओडिशा उत्तर तटीय आंध्रप्रदेश और उससे लगे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है, इसके साथ ऊपरी हवा एक चक्रवाती सिस्टम समुद्र तल से 7.6 किमी ऊंचाई तक विस्तारित फैला हुआ है।

शाह के लगातार दौरों से सत्तारूढ़ दल चौकन्ना

हाईलेवल मीटिंग में आज खुलेगा गुटबाज नेताओं का कच्चा-चिट्ठा!

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरों ने सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के कान खड़े कर दिए हैं। शाह का एक ही महीने में यह तीसरा दौरा है। प्रदेश के आला नेताओं के साथ अमित शाह की आज शाम अहम् बैठक होनी है। इस बैठक में संगठनात्मक रिपोर्टों पर चर्चा होने के साथ ही चुनावी घोषणा-पत्र के पहलुओं व गुटबाज नेताओं की वजह से हो रहे नुकसान को लेकर भी अहम् विमर्श होने की संभावना है। पिछली दफा जब केन्द्रीय मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था, तब उन्होंने प्रादेशिक नेताओं को कई होमवर्क दिए थे। अब वे इस पर हुई प्रगति की रिपोर्ट भी लेंगे। चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर तो चर्चा होनी ही है।

विधानसभा चुनाव का वक्त जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों की सरगर्मियां भी उसी तेजी से बढ़ रही हैं। सत्तारूढ़ दल कांग्रेस ने पॉवर गेम शुरू कर दिया है तो दूसरी ओर विपक्षी दल भाजपा में अलग ही तरह का राजनीतिक माहौल तैयार किया जा रहा है। चुनाव को लेकर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हाईलेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए शाह शनिवार शाम खुद रायपुर आ रहे हैं।

लगातार तीसरा दौरा

अमित शाह 22 जून को छत्तीसगढ़ के प्रवास पर थे। इस दिन वे दुर्ग में आयोजित सभा में शामिल हुए थे। इसके बाद वे 5 जुलाई को प्रदेश भाजपा कार्यालय ए थे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक ली थी। आज की हाईलेबल मीटिंग में शाह घोषणा-पत्र समिति के सदस्यों व भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही चुनावी रणनीति पर मार्गदर्शन भी करेंगे। सूत्रों की मानें तो पांच व छह जुलाई को रायपुर प्रवास के दौरान शाह ने प्रदेश के नेताओं को होमवर्क दिया था। उन्होंने प्रदेश भाजपा प्रभारी माथुर और सह प्रभारी नितिन नबीन को एक प्रारूप दिया था। इस प्रारूप के आधार पर हर विधानसभा क्षेत्र की जानकारी एकत्रित करने को कहा गया था। इसी विधानसभावार रिपोर्ट पर शाह मंथन करेंगे। बताते हैं कि शाह के पास पहले से ही कई तरह की सर्वे की रिपोर्ट है। इन रिपोर्टों की वास्तविकता को वे माथुर व नवीन से मिले तथ्यों के साथ मिलाकर यह भावी राजनीतिक हालातों की खबर लेंगे।

मांग सकते हैं स्पष्टीकरण

अमित शाह छत्तीसगढ़ के मुद्दों के बारे में पार्टी नेताओं से फीडबैक लेंगे और कुछ मसलों पर स्पष्टीकरण भी मांग सकते हैं। वे संकल्प पत्र बनाने को लेकर टिप्स भी दे सकते हैं और पार्टी आलाकमान को मिले फीडबैक को शेयर भी कर सकते हैं। बता दें कि, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने अपने सबसे भरोसेमंद और विश्वस्त सहयोगी ओम माथुर को प्रदेश का प्रभारी बना कर छत्तीसगढ़ भेजा था और हाल ही में पार्टी ने उन्हें राज्य का चुनाव प्रभारी भी बना दिया है। बताया जा रहा है कि ओम माथुर ने छत्तीसगढ़ के अलग-अलग इलाकों का दौरा कर हाल ही में अमित शाह को पूरी रिपोर्ट दी थी। यह रिपोर्ट भी बैठक का एजेंडा रह सकता है।

चुनाव कैम्पेन पर फोकस

माना जा रहा है कि इस बैठक में अमित शाह यह तय कर सकते हैं कि राज्य के किस नेता को विधानसभा चुनाव के लिए कैम्पेन-सी जिम्मेदारी देनी है। इसके साथ ही शाह पार्टी के सीनियर नेताओं की सक्रियता पर उठ रहे सवालों पर भी चर्चा कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के मुद्दे क्या होंगे, इसके साथ-साथ कैंपेन को किस तरह से चलाना है इस पर भी मंथन हो सकता है। गौरतलब है कि शाह ने हाल ही में प्रादेशिक नेताओं को आक्रामक राजनीति करने की नसीहत दी थी। माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में छत्तीसगढ़ भाजपा, पश्चिम बंगाल की तर्ज पर चुनाव संचालन कर सकती है।

अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली है। जानकारों का कहना है कि अमित शाह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कमान संभाल ली है। यहीं कारण है कि एक महीने के अंदर वो तीसरी बार राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह इस बैठक में पार्टी के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही आगे की रणनीति भी तय करेंगे। हाल ही में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने राज्य का दौरा कर अपनी रिपोर्ट संगठन को दी थी। इस रिपोर्ट पर भी शाह, प्रादेशिक नेताओं से विचार-विमर्श करेंगे। शाह का छत्तीसगढ़ दौरा कई मायनों में अहम रहने जा रहा है। बताया जा रहा है कि रायपुर में शाह प्रदेश चुनाव प्रभारी ओम माथुर, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों पर ही चर्चा करेंगे। इसके साथ-साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र यानी चुनाव घोषणा पत्र बनाने को लेकर भी अहम चर्चा होगी।

अमृत भारत स्टेशन योजनाः छत्तीसगढ़ के 30 रेलवे स्टेशन बनेंगे मॉडल

राज्यसभा में रेलमंत्री ने बताया क्या है इसका प्लान

रायपुर। भारत सरकार द्वारा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर शोर से काम किया जा रहा है। देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों को सुविधाजनक बनाया जा रहा है। साथ की छोटे व मध्यम रेलवे स्टेशनों को भी मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत उन्नयन व विकास के लिए देश के 1309 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। खासबात यह है कि इस योजना में इस योजना में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 49 स्टेशन शामिल है। अकेले छत्तीसगढ़ से 30 रेलवे स्टेशनों को इस सूची में शामिल किया गया है।

शुक्रवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के दौरान रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है।

योजना में शामिल हैं एसईसीआर के यह रेलवे स्टेशन

इस योजना के तहत अब तक 1309 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है, जिनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 49 स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों में छत्तीसगढ़ के 30,मध्य प्रदेश के 9, महाराष्ट्र के 8 और ओड़िशा के 2 स्टेशन शामिल हैं । इसमें बिलासपुर, रायगढ़, बाराद्वार, चांपा, नैला, अकलतरा, कोरबा, उसलापुर, पेंड्रारोड, बैकुंठपुर रोड, अंबिकापुर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, बिजुरी, ब्रजराजनगर, बेलपहाड़, दुर्ग, भिलाई पावर हाउस, भिलाई, बालोद, दल्ली राजहरा, भानुप्रतापपुर, सरोना, मरोदा, मंदिर हसौद, उरकुरा, भिलाई नगर, बिल्हा, निपानिया, भाटापारा, हथबंद, तिल्दा नेवरा, रायपुर, बालाघाट, चंदाफोर्ट, छिंदवाड़ा, गोंदिया, राजनन्दगांव, डोंगरगढ़, भंडारा रोड, नैनपुर, इतवारी, कामठी, मांडलाफोर्ट, सिवनी, तुमसर रोड, वडसा, आमगांव आदि स्टेशन शामिल हैं।

मास्टर प्लान तैयार

रेलमंत्री वैष्णव ने बताया कि इसमें स्टेशन पहुंच, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, आवश्यकतानुसार लिफ्ट, एस्केलेटर, स्वच्छता, मुफ्त वाई-फाई, स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क जैसी सुविधाओं में सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणों में उनका कार्यान्वयन शामिल है। ऐसे प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 'एक स्टेशन एक उत्पाद', बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, कार्यकारी लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामांकित स्थान, भूनिर्माण आदि जैसी योजनाएं शामिल है।

पोटेनार के जंगल में पुलिस-नक्सलियो में मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में भागे नक्सली

श्रीकंचनपथ न्यूज

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर में आज शनिवार तड़के सुबह पोटेनार के जंगल- पहाड़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। ग्राम पोटेनार एवं केशामुंडी के जंगल-पहाड़ में भैरमगढ़ एरिया कमेटी के 10-15 सशस्त्र नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर जांगला से संयुक्त दल रवाना हुआ था।

पुलिस पार्टी में डीआरजी, बस्तर फाइटर एवं सीआरपीएफ 222 के जवान शामिल रहे। जंगल में पुलिस पार्टी को देख माओवादियों द्वारा फायरिंग की गई। जवानों द्वारा जवाबी कार्रवाई से नक्सली भागने में सफल हुए। सुरक्षा बलों द्वारा मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में सर्चिंग अभियान जारी है। ये जिले के जांगला थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। इस घटना की एसपी आंजनेय वार्ष्णेय ने पुष्टि की है।

बंगाल में चोरी को लेकर 2 आदिवासी महिलाओं को किया निर्वस्त्र, बाल खींचकर चप्पलों से पीटा

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोलकाता। मणिपुर में 19 जुलाई को दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने का वीडियो वायरल हुआ था। अब ऐसी ही एक घटना पश्चिम बंगाल के मालदा में सामने आई है। यहां भीड़ ने दो महिलाओं की पिटाई की, फिर उन्हें अर्धनग्न कर दिया गया।

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाओं का एक समूह दो

महिलाओं को घेरे हुए है। उनके बाल खींचकर चप्पलों से पिटाई की जा रही है। इसके बाद उनके बुरी तरह से कपड़े फाड़ दिए गए। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

अमित मालवीय के मुताबिक, यह घटना मालदा के बामनगोला पुलिस स्टेशन के पाकुआ हाट इलाके में हुई। दोनों पीड़ित महिलाएं आदिवासी हैं। मालवीय ने आरोप लगाया कि, जब उनकी पिटाई हो रही थी और कपड़े उतारे जा रहे थे तो पुलिस वहां मूकदर्शक बनी खड़ी हुई थी।

विपक्ष के वॉकआउट पर रात 1 बजे ध्वनिमत से गिरा अविश्वास प्रस्ताव

सीएम बोले- अब बस्तर में रिश्ता करने में दिक्कत नहीं होती

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। विपक्ष की ओर से छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव रात 1 बजे ध्वनिमत से अस्वीकृत कर दिया गया। सीएम भूपेश बघेल ने अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में जवाब देते हुए कहा कि भेंट मुलाकात के दौरान मैंने बस्तर में रात बिताई। वहां सभी से मिला। इस दौरान जो सबसे बड़ा कमेंट मिला, वो मेरे दिल को छू लिया। जैन समाज के लोगों से मैंने पूछा कि इन चार सालों में क्या फर्क आया। उन्होंने कहा कि रिश्ता करने में अब बस्तर में दिक्कत नहीं होती है। आसानी से लोग रिश्ता दे देते हैं।

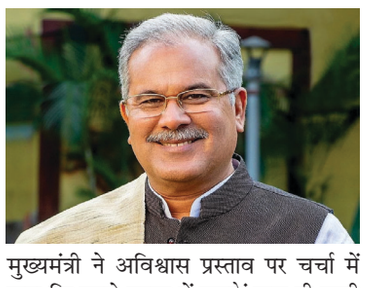

मुख्यमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में कहा कि पहले बस्तर में सड़कें काट दी जाती थी, आज सड़के काटी नहीं जाती, ये परिवर्तन बस्तर में देखने को मिला है। पिछली सरकार ने जो स्कूल बंद करा दिए थे, उसे हमने शुरू करवाया। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दों में कोई तथ्य नहीं है। प्रजातंत्र में विपक्ष का अधिकार होता है कि वे अविश्वास करे। सत्ता पक्ष के पास भी मौका होता है कि अपनी बात रखें। इन्होंने 109 आरोप लगाए पर कोई तथ्य नहीं दिए। पहले जब अविश्वास प्रस्ताव आता था तब नक्सली समस्या पर पहले बात होती थी। इस बार सदस्यों ने नही की। ये हमारी उपलब्धि है। आप इंद्रावती के उस पार गए क्या ये संभव था। ये इसलिए हुआ कि इस समस्या पर काम हुआ।

राशन पहुंचाना पहले टेढ़ी खीर थी, अब आसान

उन्होंने कहा कि राशन पहुंचाना भी पहले टेढ़ी खीर थी। अब कितना आसान हो गया है। ये बदलाव आया है। जब हमारी सरकार बनी तो हमने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की बात की। उन महापुरुषों को, कलाकारों और राजनीतिक दलों के लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने छत्तीसगढ़ निर्माण में अपना योगदान दिया। परिवर्तन केवल सत्ता के लिए नहीं होना चाहिए। यह लोगों के जीवन मे होना चाहिए इसलिए परिवर्तन की मशाल लेकर हमारे नेता परिवर्तन यात्रा में निकले थे। आज हमने किसानों की जिंदगी बदली है। बस्तर, सरगुजा में परिवर्तन हुआ है। महिलाओं के जीवन मे बदलाव आया है। जब बच्चे फर्राटेदार इंग्लिश में बोलते हैं तब संतोष होता है।

अविश्वास प्रस्ताव लाकर करवा ली बेइज्जती

श्रीकंचनपथ

छत्तीसगढ़ विधानसभा के आखिरी सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने आखिर अपनी बेइज्जती करवा ही ली। बहस में कल के विधायकों ने कद्दावरों को सड़कछाप तक कह दिया। प्रत्येक वार पर ऐसा पलटवार हुआ कि विपक्ष को अपनी लज्जा बचाने के लिए सदन छोड़कर भागना पड़ा। वैसे भी ये सभी चुनावी आरोप-प्रत्यारोप थे। ये जुमलेबाजी है। 40-50 साल पहले लोग हजारों के घोटाले की बातें करते थे। हजार पर जोर देने के लिए उसे हज्जार कहने का चलन हुआ। फिर लाखों के घोटाले होने लगे, अब करोड़ों नहीं बल्कि हजारों करोड़ के घोटाले होते हैं। 10-15 हजार की मासिक पगार पर घर चलाने वालों को ये आंकड़े अब ज्यादा प्रभावित नहीं करते। वह तो परेशान इसलिए है कि रसोई गैस, पेट्रोल, केबल टीवी, मोबाइल रिचार्ज सबकुछ महंगा हो गया है। पांच हजार रुपए तो इसी में खर्च हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कम से कम बिजली बिल में राहत तो दी है। इसे भी विपक्ष फ्री-बी बता रहा है। सनातन की हिमायती पार्टी भी जब जुमलेबाजी पर आती है तो उसे भी अंग्रेजी के 'स्लैंग' (चालू भाषा) का उपयोग करना पड़ता है। वैसे भी यह पार्टी प्रवचन पंडालों में ज्यादा जाती है। प्रवचनकारों में इन दिनों नया ट्रेंड शुरू हो गया है। अब वे राम-रावण, या राम-सीता की बातें नहीं करते। अब उन्हें उन तमाम राक्षसों के नाम याद आ रहे हैं, जिनका वध प्रभु श्रीराम ने किया था। विपक्ष इसी को फॉलो कर रहा है, पर प्रवचनकार दो बातें भूल जाते हैं। पहला तो यह कि वह त्रेतायुग था और यह कलियुग है। दूसरा यह कि इनमें से अधिकांश राक्षस प्रभु श्रीराम के हाथों प्राण गंवाकर शापमुक्त हुए थे। वैसे भी आरोप पत्र की लंबाई चौड़ाई देखकर शादी कार्ड के दर्शनाभिलाषियों की सूची याद आ गई। इस सूची में अति-उत्साही उन बच्चों का भी नाम डलवा देते हैं जो अभी केवल 'मां बोल पाते हैं। वो हजार-पांच सौ तो क्या, किसी भी अपरिचित के दर्शन के अभिलाषी नहीं होते। फिर भी उनका नाम वैवाहिक पत्रिका पर छप जाता है। इनमें से कईयों का तो अभी नामकरण तक नहीं हुआ होता ङ्क गोलू-मोलू-चिंटू-पिंटू लिखकर काम चलाया जाता है। आरोपों की सूची लंबी करने के झोंक में विपक्ष ने उन मुद्दों को भी इसमें जोड़ दिया जो खुद उनके कार्यकाल के थे। ऐसा ही एक मुद्दा था किसानों की राशि के गबन का। वैसे इस लंबी सूची की कोई जरूरत नहीं थी। चार-छह सॉलिड मुद्दे लेकर आते। अच्छी तैयारी के साथ आते और जमकर बहस करते तो जनता निहाल हो जाती। पर विपक्ष तो 15 साल सत्ता में रहकर खुद को ही शेर समझ बैठा था। वह भूल गया था कि जो पार्टी अभी सत्ता में है वह देश की सबसे पुरानी पार्टी है। उसमें भी ऐसे विधायक हैं जो पिछले 35 साल या उससे भी अधिक समय से विधानसभा के सदस्य हैं। जुबान उनके मुंह में भी है।

संपादकीय

त्वरित न्याय के लिए

भारतीय अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पांच करोड़ से ऊपर जाने लगी है, तो यह चिंताजनक है। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया है कि भारतीय अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या 5.02 करोड़ से ज्यादा हो गई है। लंबित मामले हमारे लिए निरंतर चिंता का विषय बने हुए हैं। अकेले सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 69,766 हो गई है। एक अनुमान के अनुसार, भारत में दस में से नौ मामले अदालतों में लंबित रहते हैं। केवल दस प्रतिशत मामलों में ही त्वरित कार्यवाही चल पाती है। आखिर इतने मामले क्यों लंबित हैं? इसका एक पहलू यह भी है कि लोग पहले की तुलना में अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा सजग हुए हैं, इसलिए अदालत पहुंचकर अपना अधिकार लेने की चेष्टा कर रहे हैं। वैसे बढ़ती जागरूकता जहां अच्छी बात है, वहीं मामलों का लंबित रहना बड़ी चिंता की बात है। ध्यान रहे, लोग न्याय की प्रत्याशा में ही अदालत का रुख करते हैं। ऐसे में, अगर उन्हें जल्दी न्याय नहीं मिलेगा, तो वे दूसरे रास्ते अपनाएंगे, जो देश में कानून-व्यवस्था की सेहत के लिए ठीक बात नहीं होगी। लंबित मामलों पर चिंता पहले भी कई बार उठी है। पिछले वर्ष जुलाई में भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने देश में ज्यादा लंबित मामलों पर तत्कालीन कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का जवाब देते हुए कहा था कि न्यायिक रिक्तियों को न भरना इसका प्रमुख कारण है। तब भी यह चिंता जताई गई थी कि लंबित मामलों की संख्या पांच करोड़ को पार करने वाली है, पर अब जब वाकई पार कर गई है, तो सभी संबंधित पक्षों को सजग हो जाना चाहिए। लंबित मामलों को जल्द से जल्द न्याय तक पहुंचाने के लिए सरकार और न्यायपालिका के बीच अच्छा समन्वय होना चाहिए। पिछले साल ही देश के प्रधान न्यायाधीश ने केंद्रीय मंत्री को कह दिया था कि न्यायिक रिक्तियों को भरना और न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार करना जरूरी है। क्या विगत एक वर्ष में इस दिशा में गंभीरता से काम हुआ है? दिसंबर 2022 तक देश के 25 उच्च न्यायालयों में जजों की संख्या होनी चाहिए थी 1,108, पर जज थे 778 कुल। निचली अदालतों की बात करें, तो जजों के पद थे 24,631 और जज थे 19,288 मात्र। इतने पद खाली कैसे हैं? आज जरूरत समग्रता में सोचने की है। मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे, बताया जा रहा है, मणिपुर में ही 3 मई के बाद हुए दंगों के चलते 6,000 से अधिक एफआईआर दर्ज हुए हैं, इनमें से ज्यादातर मामले अदालतों में जाएंगे और दोषियों को सजा मिलने में न जाने कितना समय लगेगा? यदि मणिपुर में तत्काल प्रभाव से कानून का राज कायम करना है, तो अदालतों को भी त्वरित न्याय करना होगा। अपराधी लंबित मामलों में अपने बचाव की गुंजाइश देखते हैं, जबकि पीड़ित को सालों बाद जब न्याय मिलता है, तो न्याय अपना महत्व लगभग खोकर समाज में अन्याय को बढ़ावा देता है। त्वरित न्याय पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी है। न्याय और वह भी त्वरित न्याय का माहौल बनाने की कोशिश में हम चीन जैसी तानाशाही व्यवस्था का अनुसरण नहीं कर सकते, पर अपनी लोकतांत्रिक सीमाओं में रहते हुए न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के हरसंभव उपाय तो कर ही सकते हैं। भारत जैसी विशाल आबादी वाले देश-समाज में अमन-चैन के लिए यही होना चाहिए।

> आज जरूरत समग्रता में सोचने की है। मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे, बताया जा रहा है, मणिपुर में ही 3 मई के बाद हुए दंगों के चलते 6,000 से अधिक एफआईआर दर्ज हुए हैं, इनमें से ज्यादातर मामले अदालतों में जाएंगे और दोषियों को सजा मिलने में न जाने कितना समय लगेगा? यदि मणिपुर में तत्काल प्रभाव से कानून का राज कायम करना है, तो अदालतों को भी त्वरित न्याय करना होगा।

गरीबी पर बहस हो

ऐसी रिपोर्ट के साथ यह सवाल जुड़ा होता है कि इसे जारी करने का मकसद असल सूरत को सामने लाना है ताकि गरीबी उन्मूलन की दिशा में प्रगति हो सके- या अपनी सफलता का बखान करना?

पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया था, जिसमें बताया गया कि इस पैमाने पर भारत में गरीबों की संख्या घटकर 16.4 रह गई है। सोमवार को नीति आयोग ने इसी पैमाने पर अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि भारत में 2019-21 में घटकर 14.96 प्रतिशत रह गई है। दोनों रिपोर्टों में बताया गया कि उन्होंने अपनी गणना को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 को आधार बनाया गया है। तो आखिर यह अंतर कैसे आ गया? यह अंतर इसलिए आया कि नीति आयोग ने दो नए पैमाने जोड़े। उसने प्रसव के समय मातृ मृत्यु दर और बैंक खातों को भी गरीबी मापने का आधार बनाया। इसके अलावा रसोई गैस की उपलब्धता जैसे आधार का वजन बढ़ा दिया गया। उससे लगभग डेढ़ प्रतिशत का फर्क पड़ गया। यह अंतर ये भी बताता है कि गरीबी मापने में अगर कुछ भी हेरफेर कर दी जाए, तो संख्या में भारी फर्क पड़ सकता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरीबी दर में सबसे तेज कमी देखी गई।

बहुआयामी गरीबी पैमाने पर भारत में 2015-16 में 24.85 प्रतिशत लोग गरीब थे, जो संख्या 2019-21 में 14.96 प्रतिशत हो गई। यानी पांच साल में गरीबी 9.89 प्रतिशत घटी है। यह भी दावा किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 32.59 प्रतिशत से घटकर 19.28 प्रतिशत हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में गरीबी 8.65 प्रतिशत से घटकर 5.27 प्रतिशत हो गई। लेकिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानताएं बनी हुई हैं। शहरी क्षेत्रों में 5.27 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण आबादी का 19.28 प्रतिशत बहुआयामी रूप से गरीब है। बहरहाल, ऐसी रिपोर्ट के साथ यह सवाल जुड़ा होता है कि इसे जारी करने का मकसद असल सूरत को सामने लाना है ताकि गरीबी उन्मूलन की दिशा में प्रगति हो सके- या अपनी सफलता का बखान करना? खासकर यह सवाल इसलिए बरबस उठ जाता है, जब आंकड़ों से खिलवाड़ होता हुआ नजर आता है।

चुनावी मुकाबले में 'इंडिया'

बयान में कहा गया है कि 'इंडिया' रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका को बहाल करेगा। यह एक बड़ा वादा है। इसे पूरा करने की नए गठबंधन के पास क्या रणनीति है, इसका संकेत संभवत: उसके साझा न्यूनतम कार्यक्रम में मिलेगा। छब्बीस विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम कुछ इस ढंग से रखा, जिससे उसका शॉर्ट फॉर्म 'इंडिया' बने। इस तरह उन्होंने भारत के मतदाताओं के मन को छूने की कोशिश की है। इस प्रयास में उन्होंने दो शब्द अपने नाम के फुल फॉर्म में जोड़े- डेवलपमेंटल और इन्क्लूसिव। इस तरह इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस (इंडिया) बना। अगर थोड़ा पीछे मुड़ कर देखा जाए, तो जब यूपीए का शासन था, तब इन्क्लूसिव डेवलपमेंट शब्द काफी प्रचलित था। यूपीए ने अपनी विकास दृष्टि को इसी शब्द से व्यक्त किया था, जो वैसे नव-उदारवादी नीतियों के साथ सारी दुनिया में पहुंचा था। अर्थ यह है कि जो विकास हो, वह समावेशी हो। यानी उसके लाभ सभी तबकों तक पहुंचें। इसके लिए यूपीए के जमाने में एक सोशल एजेंडा अपनाया गया था, जिसे कार्यरूप देने के लिए सोनिया गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाई गई थी।

> कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासनिक कागजों पर नियमों की भरपाई होती है। एक से बढ़कर एक नियम बनाए जाते हैं। डाक कांवड़ की ऊंचाई तय की जाती है, डीजे के नियम बनाए जाते हैं। सबके पहचान-पत्र और रजिस्ट्रेशन की दलीलें दी जाती हैं। मगर इस बार भी कांवड़िये दौड़ते रहे और प्रशासन हांफता रहा। पूरी सरकारी मशीनरी 20 दिन इसी काम में लगी रही कि कानून-व्यवस्था बनी रहे और शांति से कांवड़ यात्रा पूरी हो जाए।

सावन में कांवड़मय हुए राज्यों की बढ़ती चुनौतियां

सूर्यकांत द्विवेदी, स्थानीय संपादक, मेरठ हिन्दुस्तान

आसमानी आफत और आस्था साथ-साथ चलती है। सावन का महीना आते ही सांसें तेज हो जाती हैं। हो भी क्यों न? कांवड़ यात्रा जो प्रारंभ होती है। साल-दर-साल कांवड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले साल यह आंकड़ा चार करोड़ का था, जो इस साल बढकर पांच करोड़ हो गया। चूंकि इस बार दो सावन हैं, इसलिए संख्या और बढ़ सकती है। 2010 में सवा करोड़ कांवड़िये हरिद्वार पहुंचे थे, जबकि 2019 में 3.30 करोड़ और 2022 में 3.80 करोड़। सावन के इस महीने में दस से अधिक राज्य किसी न किसी रूप से कांवड़मय होते हैं। हरिद्वार से गंगायात्रा प्रारंभ होती है। इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल होते हैं। बिहार, झारखंड में अलग से यह यात्रा होती है। राज्यों की भागीदारी और पांच करोड़ कांवड़ियों की भीड़ के आगे शासन-प्रशासन नतमस्तक है। पहले खड़ी या बैकुंठी कांवड़ चलती थी। भीड़ के बावजूद व्यवस्था संभाल ली जाती थी, पर अब डाक कांवड़ ने चुनौती बढ़ा दी है। डाक कांवड़, यानी बड़ी-बड़ी झांकियों के साथ, दौड़ते-भागते हरिद्वार से समूह में गंगाजल लाने की नई परंपरा चल पड़ी है। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, हरिद्वार से गंगाजल लेने वाले पांच करोड़ कांवड़ियों में करीब तीन करोड़ डाक कांवड़ थे।

कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासनिक कागजों पर नियमों की भरपाई होती है। एक से बढ़कर एक नियम बनाए जाते हैं। डाक कांवड़ की ऊंचाई तय की जाती है, डीजे के नियम बनाए जाते हैं। सबके पहचान-पत्र और रजिस्ट्रेशन की दलीलें दी जाती हैं। मगर इस बार भी कांवड़िये दौड़ते रहे और प्रशासन हांफता रहा। पूरी सरकारी मशीनरी 20 दिन इसी काम में लगी रही कि कानून-व्यवस्था बनी रहे और शांति से कांवड़ यात्रा पूरी हो जाए। यह नजारा किसी एक जिले का नहीं, न ही एक प्रदेश का है। सभी प्रदेशों में अपने रंग, अपने ढंग और परंपरानुसार यह सब हो रहा है।

दरअसल, कांवड़ यात्रा को अब कुछ और दृष्टिकोण से भी समझना होगा। यह केवल आस्था का सवाल नहीं है। इसके साथ जुड़ी हैं कई चुनौतियां। लाभ-हानि को अलग करके विचार करें, तो पाएंगे कि मंदिर समितियों के बूते से कांवड़ यात्रा बाहर हो गई हैं। अस्सी के दशक में कांवड़ यात्रा की व्यवस्थागत जिम्मेदारी मंदिर समितियों की होती थी। अब उनकी क्षमता जवाब दे गई है। ढेर सारी प्रशासनिक व्यवस्था अकेले प्रशासन भी नहीं कर सकता, न ही किसी एक प्रदेश की सरकार। इस पर सामूहिक रूप से सभी संबंधित राज्यों को मिलकर रणनीति बनानी होगी। ऐसे उपाय करने होंगे कि लोकजीवन सामान्य चलता रहे और कांवड़ यात्रा भी होती रहे। ठीक वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा की तरह। बाकायदा इसके लिए कांवड़-यात्रा बोर्ड बने। कांवड़ यात्रा का मार्ग अधिसूचित हो। बजट का निर्धारण हो। कांवड़ियों का बीमा और पंजीकरण हो। यानी, समस्त वे व्यवस्थाएं हों, जो अन्य यात्राओं में होती हैं। दुर्भाग्य यह है कि इतनी बड़ी यात्रा को संभालने के लिए व्यवस्था बौनी है। मंदिर समितियों और प्रशासन में कोई तालमेल नहीं होता। प्रशासन के लिए करोड़ों की संख्या शिवालयों तक पहुंचते-पहुंचते लाखों में हो जाती है। जैसे, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने कांवड़ियों की संख्या पांच करोड़ बताई, पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मंदिर समितियों का आंकड़ा एक करोड़ भी नहीं पहुंचा। आखिर बाकी कांवड़िये कहां गए?

उत्तराखंड सरकार इन कांवड़ियों को शिव भक्त के साथ-साथ पर्यटक के रूप में गिनती है। यदि एक कांवड़िये ने एक हजार रुपये भी खर्च किए, तो सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना सरकारी खजाना भरा होगा। कांवड़ यात्रा की चुनौतियों को लेकर संसद में सवाल भी उठ चुके हैं। जन-प्रतिनिधि यह मानते हैं कि कुंभ की तरह अब हमको व्यवस्था करनी होगी। बीस दिन तक यात्रा से यातायात नहीं रोका जा सकता। सरकारी राजस्व का मोटा नुकसान होता है। फिर, एक चुनौती आसमानी आफत भी है। न मौसम को बदला जा सकता है और न ही धार्मिक कैलेंडर को। मगर लोकजीवन की रक्षा के लिए हम कुछ आपदा प्रबंधन कर सकते हैं। जिस वक्त ये यात्राएं होती हैं, उस वक्त बारिश का आलम होता है, पहाड़ों का मलबा सड़कों पर आता है, नदियां उफान पर होती हैं। इसलिए, देर सबेर हमें यह भी सोचना होगा कि आपदा में आस्था की चुनौती से कैसे निपटा जाए?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

बाढ़ पर पूरा नियंत्रण कभी नहीं हो सकता

के एल राव, तत्कालीन केंद्रीय सिंचाई व विद्युत मंत्री

माननीय सदस्यों ने उपयोगी सुझाव दिए हैं। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि बाढ़ पर पूरी तरह नियंत्रण कभी नहीं किया जा सकता। विश्व के किसी भी भाग में ऐसा नहीं हो सका है। इस वर्ष वर्षा अधिक होने के कारण नदियों में अधिक बाढ़ आई है। अधिक वर्षा के परिणामस्वरूप मकानों का गिरना और पहाड़ों का टूटना स्वाभाविक है। इस वर्ष अभूतपूर्व वर्षा के कारण बहुत व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और सामान्य बाढ़ से होने वाली क्षति की अपेक्षा इस वर्ष बहुत अधिक क्षति हुई है। बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के बारे में हमारे देश में प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है। इसके लिए 7 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अनेक छोटे—छोटे केंद्र स्थापित किए गए हैं। बाढ़ चेतावनी व्यवस्था का कार्य सही रूप से चल रहा है। उक्त व्यवस्था अनेक लोगों का जीवन बचाने में सहायक सिद्ध हुई है। इस वर्ष अधिक मकानों के गिरने से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य सरकारों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कच्चे मकानों में रहने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार बचाया जाए। प्रत्येक गांव में कुछ ऐसे मकान बनाए जाने चाहिए, ताकि ज्यादा वर्षा होने पर कच्चे मकानों में रहने वालों को वहां रखा जा सके।

कुछ सदस्यों ने रिपोर्ट के सही न होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष के आंकड़े पिछले वर्षों के आंकड़ों से मेल नहीं खाते। अभी हमें रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। कुछ राज्य इस बारे में पूरी जानकारी नहीं दे पाए हैं, क्योंकि बहुत से क्षेत्र अभी भी बाढ़ग्रस्त हैं। अत: बाढ़ से हुई क्षति का अनुमान लगाना कठिन है। कुछ लोगों ने यह विचार व्यक्त किए हैं कि बाढ़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई। साल 1954 के बाद बाढ़ नियंत्रण के बारे में हमने राष्ट्रीय नीति अपनाई है और हम अब विभिन्न भागों में किए गए सभी प्रयासों को समन्वित कर रहे हैं, जो किसी भी क्षेत्र के लिए उपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं। 1954 के बाद बाढ़ से होने वाली क्षति में एक तिहाई कमी हुई है। आगामी दस वर्षों में इस क्षति में 50 प्रतिशत की कमी करने के लिए सरकार कार्रवाई करेगी। बाढ़ नियंत्रण के बारे में हम सामान्य योजना पूरी करना चाहते हैं, जिससे बाढ़ ग्रस्त होने वाले कुछ क्षेत्रों की रक्षा की जा सके। उड़ीसा राज्य में हम बाढ़ पर नियंत्रण पाने में काफी सफल हुए हैं।

असम राज्य की समस्या बड़ी कठिन है। इस बारे में अनेक विदेशी इंजीनियरों की सलाह ली गई है। हम उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि हम ब्रह्मपुत्र पर बांध का निर्माण भी करें, तो भी हम बाढ़ पर नियंत्रण पाने में सफल नहीं होंगे। कटाव की समस्या भी बड़ी कठिन है। भारत सरकार ने यह अनुभव किया है कि ब्रह्मपुत्र की समस्या पर निरंतर निगरानी रखने की जरूरत है। असम राज्य अकेले इस समस्या को हल करने में सक्षम नहीं है। सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि ब्रह्मपुत्र नदी बोर्ड को केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होनी चाहिए। इस बारे में अगले सत्र में विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। डिब्रुगढ़ का कटाव भी कठिन समस्या है। नगर की रक्षा के लिए हमने कई करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इस समस्या का अध्ययन करने के लिए हमने ब्रिटिश विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था। उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर हमने कार्रवाई करने का निर्णय किया है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरीबी का मुख्य कारण यह है कि वहां बाढ़ पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। घाघरा और रापी नदियां देश के विभिन्न भागों में भारी विनाश कर रही हैं। जनता की रक्षा के लिए हमें गांवों की सतह को ऊंचा करना होगा। हमने लगभग 4,000 गांवों की सतह को ऊंचा किया है। ये काफी सुरक्षित स्थान बन गए हैं और लोग वहां रहते हैं...। करगली में घाघरा और जलकुंडी में रापी नदी पर बांध बनाकर समस्या को हल किया जा सकता है। ये दोनों स्थान नेपाल में हैं। इन दोनों नदियों पर बांध बनाए बिना बाढ़ पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता।... पंजाब में बाढ़ की समस्या इतनी गंभीर नहीं है, जितनी जल निकासी की है। सतलुज और रावी बांध में दरारें पड़ गई हैं, लेकिन इन दरारों से अधिक क्षति नहीं हुई हैं। पोंग बांध के पूरा हो जाने पर शायद अगामी वर्ष में व्यास नदी के जल पर पूर्ण नियंत्रण हो सकेगा, इसके बाद कुछ ही नदियां रह जाती हैं।...

हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हम बाढ़ नियंत्रण के लिए यथोचित कार्रवाई कर रहे हैं। आशा है, आगामी वर्ष में हम राष्ट्र की और अच्छी सेवा कर सकेंगे।

(लोकसभा में दिए गए भाषण का अंश)

सूखे से शुरू हुआ सत्र और बाढ़ पर समापन

विश्वनाथ प्रताप सिंह, वरिष्ठ सांसद

महोदय, हमने इस संसद सत्र की शुरुआत सूखे पर चर्चा के साथ की थी और इसके अंत में हम बाढ़ पर चर्चा कर रहे हैं। प्रकृति की इन दो विपरीत आपदाओं में केवल एक चीज समान है और वह है जनता का दुख। हर सुबह, हमारे अखबारों में देश के कोने-कोने से, कश्मीर, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से दुख की कहानियां छपकर आती हैं। अगर एक खबर हमारे लिए शोक संतप्त लोगों की सिसकियां लेकर आती है, तो दूसरी खबर हमारे लिए लाती है बेघर हो चुके लोगों का विलाप, और हर सुबह व्यापक फसल क्षति की निराशाजनक खबर सामने आती है।

हालात ऐसे हो गए हैं कि...अब तो राजस्थान भी बाढ़ का दावा कर सकता है। और यह उत्तर प्रदेश में... बाढ़ से पहले सूखा पड़ा था। सूखे ने हमारा धान छीन लिया और अधिक बारिश ने हमारा बाजरा छीन लिया। आज उत्तर प्रदेश में जो कुछ बचा है, वह खरीफ की फसल का माफीनामा मात्र है। अखबारों के शीर्षकों की एक झलक से ही पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितना नुकसान हुआ है। बाढ़ से इलाहाबाद के 1,000 गांव तबाह हो गए हैं। इलाहाबाद जिले में पानी भर गया है और नदियों में कटाव हो गया है। कालागढ़ मशीनरी बह गई, बरेली के पास बांध के टूटने का खतरा है, उत्तर प्रदेश में नदियों में जल की वृद्धि जारी है और धन की क्षति का अनुमान है 6 करोड़ रुपये, तो यह है उत्तर प्रदेश की दुखद गाथा।

आज बाढ़ जनित मानवीय पीड़ा की तात्कालिकता हमसे तत्काल राहत की मांग कर रही है। हमें तुरंत जरूरी राहत पहुंचानी पड़ेगी और भू-राजस्व में छूट देनी पड़ेगी।। जो लोग बाढ़ से बेघर हो गए हैं, उन्हें आश्रय देना होगा और उन मजदूरों के लिए परीक्षण कार्य शुरू करना होगा, जिनके पास अभी कोई काम-धंधा नहीं बचा है।

ऐसे समय में, क्या मैं यह कह सकता हूं कि राहत कार्यों के अलावा, हमें समस्या को व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी देखना होगा। हमें ऐसी आपदा से बचाव के लिए प्रशासनिक और इंजीनियरिंग उपाय भी करने होंगे। समय कम होने के कारण मैं अभी विस्तार

से नहीं बता सकता। इसलिए, अभी मैं खुद को उत्तर प्रदेश को प्रभावित करने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक तक ही सीमित रखूंगा, और वह है गंगा नदी के किनारे होने वाला कटाव, जिसे सी पी डब्ल्यू सी ने भी अपनी रिपोर्ट में यह कहते हुए स्वीकार किया है कि ब्रह्मपुत्र के दोनों तटों पर, गंगा नदी में मिलने वाली नदियों गंडक और घाघरा के कुछ हिस्सों में गंभीर मात्रा में कटाव हो रहा है।

गांव के ऐसे क्षेत्र, जो बाढ़ के अधीन होते हैं, वहां आमतौर पर हरिजन और गरीब लोग ही निवास करते हैं। संपन्न लोग ऊंचे स्थानों पर रहते हैं, जहां ये बाढ़ सामान्यत: नहीं पहुंच पाती है। मुझे इलाहाबाद जिले की फूलपुर तहसील का लीलापुर गांव याद आ रहा है, जहां बाढ़ आने पर हरिजन आबादी चारों तरफ से पानी से घिर जाया करती है और लीलापुर के हजारों लोगों को बड़ी पीड़ा झेलनी पड़ती है।

इसके बाद मैं सड़कों, रेलवे और नहरों के कारण प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था में पैदा होने वाले व्यवधान पर आऊंगा। उचित ढंग से पुलिया और पुलों का निर्माण नहीं किया गया है। बारिश के पानी के बहाव का पर्याप्त आंकड़ा नहीं है। यह आंकड़ा एकत्र किया जाना चाहिए। हमारे पास बाढ़ चेतावनी प्रणाली होनी चाहिए। जो गांव बाढ़ के दौरान पानी से घिर जाते हैं, उन्हें सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि बाढ़ आने पर प्रभावित आबादी को वहां से निकाला जा सके।

राहत उपायों की चर्चा करते समय, मैं यह बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद जिले में, हमने गरमियों के दौरान परीक्षण-कार्य किया था, लेकिन इसे अब रोक दिया गया है। उन्हें पुन: प्रारंभ किया जाए। विभिन्न प्रकार के ऋणों की वसूली बंद नहीं की गई है। ऋण वसूली को अभी भी जारी रखा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए।

एक माननीय, जौनपुर के सदस्य, ने उल्लेख किया है कि जहां आसपास के सभी जिलों को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है, वहीं जौनपुर को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है।...

महोदय, बाढ़ आ गई है, और आगे भी आती रहेगी, परंतु हमें आगे इस स्थिति में होना चाहिए कि जब बाढ़ आए, तो हम कह सकें कि हमने बाढ़ की चुनौतियों का दूरदर्शिता और ताकत के साथ मुकाबला किया।

(लोकसभा में दिए गए भाषण का अंश)

ट्रंप की गिरफ्तारी के बनते अवसर?

श्रुति व्यास

डोनाल्ड ट्रंप को जल्द मुकदमे का, गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। पूर्व राष्ट्रपति को एक चिट्ठी भेजी गई है। वह यह बताती है कि 2020 के चुनाव में हारने के बाद सत्ता पर काबिज रहने के हथकंडों पर उन्हे फेडरल मुकद्दमे का सामना करना पड़ेगा। इस मामले की जांच कर रहे विशेष प्रॉसिक्यूटरजैक स्मिथ ने बचावपक्ष को सूचित किया है कि जांचकर्ताओं को ट्रंप के अपराधी होने के साक्ष्य मिले।

ट्रंप ने अपनी खास शैली में सोशल मीडिया में इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जेक स्मिथ को 'पागल' बताते हुए कहा कि, उन्हें (ट्रूप) 6 जनवरी की घटनाओं की ग्रेंड जूरी द्वारा की जा रही जांच में निशाना बनाया जा रहा है। ट्रंप ने खुद लिखा है कि इस प्रकार के पत्र के बाद लगभग हमेशा गिरफ्तारी और अभियोजन होता है। ट्रंप का इन दिनों चुनावी कैंपेन ही इस बात पर है कि वे राजनैतिक बदले की कार्यवाही के शिकार हैं।

यह जेक स्मिथ द्वारा लगाया गया दूसरा अभियोग है। वे ही ट्रंप द्वारा व्हाईट हाउस से गोपनीय दस्तावेज अपने साथ ले जाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने, दस्तावेजों को वापिस लेने के सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में भी अभियोजक हैं। इसके अलावा ट्रंप पर मेनहट्टन में सन् 2016 के चुनाव के पहले एक पोर्न स्टार को चुप रहने के बदले धन दिए जाने का मामला भी है। इस मामले में उन पर फुल्टन काउंटी में जिला एटार्नी द्वारा आरोप लगाए जाने की संभावना है। वे ट्रम्प द्वारा राज्य में सन् 2020 में हुई चुनावी हार को पलटने के प्रयासों से जुड़े मामले की बी जांच कर रहे हैं।

जाहिर है ट्रंप एक के बाद एक मुकद्दमों, अपराधों के आरोपों और कानूनी झमेलों के दलदल में फंसते जा रहे हैं। बावजूद इसके राष्ट्रपति चुनाव अभियान जारी है, जिसमें वे अपने सभी रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वियों से आगे हैं। उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, इससे बेफिक्र ट्रंप चीख-चीखकर जनता को कह रहे हैं कि 2020 में उन्हें गलत तरीके से हराया गया और मुकद्दमें उन्हें ''प्रताड़ित करने के लिए हो रहे है। कुछ समय पहले उन्होंने अपने समर्थकों की एक भीड़ के आगे कहा था,''मैं आपका न्याय हूं। मैं आपका प्रतिरोध हूं।

उन्का ताजा मिले अभियोजन पत्र के बारे में कहना है- यह देश के लिए एक ''डरावनी खबर है, एक कालादिन है और बाइडन की अपने सबसे बड़े राजनैतिक विरोधी को गिरफ्तार करने की कोशिश है।

हैरानी की बात है कि इस सबके बीच ट्रंप का समर्थन बढ़ रहा है। साफ है 'मेक अमरीका ग्रेट अगेन' टोली के चलते अमिरिकी समाज विभाजित हो गया है। वे और उनके सहयोगी तमाम अनिश्चिताओं के बावजूद सन् 2024 के चुनाव में जोरदार जीत के प्रति आश्वस्त हैं।

न्यूयार्क टाईम्स में हाल में छपी एक खबर के अनुसार यदि ट्रंप 2025 में व्हाइट हाउस में वापिस लौटते हैं तो राष्ट्रपति के हाथों में और अधिक शक्तियां सौपने की योजना पर काम होगा। अभी की तुलना में राष्ट्रपति का सरकार पर सीधा नियंत्रण बहुत बढ़ जाएगा। प्रशासन इन-वेटिंग तैयार है जो वर्तमान में अमेरिका फर्स्ट पालिसी इंस्टीटयूट (एएफपीआई) नामक थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है। इसके 172 कर्मियों में से आठ ट्रंप प्रशासन की केबिनेट के सदस्य थे। इसमें 20 अन्य राजनीतिज्ञ भी नियुक्त किए गए हैं। एएफपीआई ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की तैयारी के लिएनिर्मित सबसे नया थिंक टैंक है, लेकिन यह सबसे बड़ा नही है। हेरिटेज फाउंडेशन, जिसेरोनाल्ड रीगन की 'क्रांति'की तैयारियों में अपनी भूमिका पर गर्व है, का अपना अभियान अलग है।

स्टेशन रोड, इंदिरा मार्केट, दुर्ग के प्रतिष्ठित संस्थान
विज्ञापन के लिए संपर्क करें:-
9827806026,
7869620239

Sargam
Musicals
Deals in All Kinds of Musical Instrument Sales & Repair
DURG:- Near Tarun Adlabs Station Road, Durg (C.G.) Durg, Ph. 2330588, 9826660688
RAIPUR:- Near Manju Mamta Reaustaurant, M.G. Road Raipur. Ph. 4013288, 9303876196

गंजेपन से मुक्ति मात्र 1 घंटे में
COMPLETE FAMILY SALON
हेयर रिप्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी
पहले बाद में
JITU'Z
CUT N SHINE
93009-11331
रंगोली बेंगल्स के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रानिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)

श्रीकंचनपथ

छत्तीसगढ़

इनकम TAX
ITR फाईल
बनवायें मात्र 500/- में
TDS, GST, TAX Expert
सम्पर्क- शेखर गुप्ता
9300755544
onlytds@gmail.com
WWW.ONLYTDS.COM

खास खबर

01 से 13 अगस्त तक जिले में मनाया जाएगा वजन त्यौहार

कोरबा। जिले में 06 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पोषण स्तर के आंकलन हेतु समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी आगामी 01 अगस्त से 13 अगस्त 2023 तक वजन त्यौहार का आयोजन किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने वजन त्यौहार के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इसका उददेश्य जन-जन को कुपोषण के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान सभी विकासखण्ड़ों में क्लस्टरवार वजन त्यौहार का आयोजन किया जाएगा। जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव, आंगनबाडी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 06 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वजन लेकर उनका पोषण स्तर (बौनापन तथा दुर्बलता) का माप किया जाएगा। साथ ही बच्चों के पोषण स्तर के बारे में अभिभावकों को अवगत कराते हुए उन्हें कुपोषण के संबंध में जागरूक कर, बच्चों को कुपोषण से बाहर लाने हेतु उचित परामर्श दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राप्त आंकड़ो के आधार पर जिले में कुपोषण की दर में कमी लाने हेतु लक्ष्यों का निर्धारण कर उपयुक्त कार्ययोजना बनाई जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जिले के समस्त अभिभावकों से वजन त्यौहार में बढ़-चढ़ कर भाग लेने और अपने बच्चों का वजन कराने की आग्रह किया है।

टीकाकरण के लिए यू-विन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर तैयार

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के दिशा-निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मधुलिका सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में जिले के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा मितानिनों को निर्देशित किया है भारत सरकार द्वारा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के टीकाकरण के लिए यू-विन डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इससे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण कार्ड ले जाने, अगली खुराक पर नजर रखने सहित अन्य परेशानियां खत्म हो सकती है। यू-विन प्लेटफार्म का उपयोग प्रत्येक गर्भवती महिला को पंजीकृत करने, उनके प्रसव के परिणाम को रिकार्ड करने, प्रत्येक नवजात शिशु के जन्म को पंजीकृत करने, जन्म खुराक देने एवं उसके बाद समस्त टीकाकरण कार्यक्रमों के लिये किया जाएगा। यू-विन के माध्यम से समस्त गर्भवती महिलाओ एवं शिशुओं को नाम सहित ट्रेकिंग किया जा सकेगा तथा समय पर लाभार्थियों को टीकाकरण करने में सहायता मिलेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि नियमित टीकाकरण के सुदृढ़ीकरण तथा डिजिटललाईजेशन हेतु भारत सरकार द्वारा यू-विन पोर्टल के माध्यम से मिशन इंद्रधनुष अंतर्गत प्रथम चरण 07-12 अगस्त, द्वितीय चरण 11-16 सितंबर तक, तृतीय चरण 9-14 अक्टूबर तीन चरणों में चलाया जायेगा।

जिला पंचायत सीईओ ने सेमीनार में दिये छात्रों को कैरियर गाइडेंस के टिप्स

यूपीएससी में वैकल्पिक विषय कैसे चुने और भारतीय संविधान इन दो विषयों पर रहा आज फोकस

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशन में प्रति शुक्रवार को जिला ग्रंथालय में कैरियर गाईडेंस सेमीनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमीनार का मुख्य उद्देश्य आज के युवा विद्यार्थी वर्ग को उनके कैरियर का चुनाव करने के लिए एक नई सोच एवं दिशा प्रदान करना है। युवा पीढ़ी अपने कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा भ्रमित होते रहते है।

इस सेमीनार के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा उन सभी विद्यार्थियों को उनके सोच के आधार पर उन्हें एक मंजिल तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। जिसमें जिले में पदस्थआईएएस, आईपीएसी अधिकारी उनके बीच पहुंच रहे है और उन्हें सफलता के टिप्स दे रहे है। इसी कड़ी में आज जिला पंचायत सीईओ के पद पर कार्यरत आईएएस अधिकारी जितेन्दर यादव प्रतिभागियों के बीच उपस्थित रहे। सीईओ जितेन्दर यादव ने आज उपस्थित विद्यार्थियों को यूपीएससी में वैकल्पिक विषय कैसे चुने और भारतीय संविधान इन दो विषयों पर छात्रों को मार्गदर्शन दिए। सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए उनकी सभी वैकल्पिक जानकारी के साथ पूरी लगन एवं मेहनत से पढ़ाई करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यूपीएससी वैकल्पिक विषयों में प्राप्त अंकों को अंतिम योग्यता की तैयारी के लिए माना जाता है। इसलिए यूपीएससी के लिए वैकल्पिक विषय का चुनाव सावधानी से करना चाहिए। अब उम्मीदवारों को केवल एक वैकल्पिक विषय चुनना होगा। यूपीएससी के लिए सर्वोत्तम वैकल्पिक विषय कैसे चुना जाए, इस पर एक विशेषज्ञ रणनीति के साथ काम करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, भारत के संविधान का संक्षिप्त परिचय, राज्यसभा की शक्तियां क्या होती है एवं इससे जुड़ी जानकारियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इसका अध्ययन ठीक से करना चाहिए क्योंकि यूपीएससी परीक्षा के लिए भारतीय संविधान का जानना बेहद उपयोगी है।

इस दौरान सीईओ श्री यादव ने उपस्थित विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया एवं उनकी जिज्ञासा का समाधान किया। जिला प्रशासन द्वारा वर्तमान में जिला ग्रंथालय में नि:शुल्क पीएससी कोचिंग के साथ महिला पर्यवेक्षक की तैयारियां भी करायी जा रही है।

इस अवसर पर एपीसी भुनेश्वर पटेल, केन्द्र समन्वयक मनोज पटेल, लाईब्रेरिन अशोक पटेल, दीपक सिंह सहित लाईब्रेरी के अन्य स्टॉफ एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बड़ी संख्या में युवा विद्यार्थी शामिल हुए थे।

सुदूर वनांचल क्षेत्र ग्राम बांगर में पहुंचा ईवीएम प्रदर्शन वैन

बैगा मतदाताओं को मतदान के लिए किया जागरूक

श्रीकंचनपथ न्यूज

कवर्धा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जनमेजय महोबे के मार्गदर्शन में जिले में शत प्रतिशत मतदान के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले के विधानसभा 71 पंडरिया के सुदूर वनांचल, बैगा बाहुल क्षेत्र ग्राम बांगर के मतदान केन्द्र में मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने आज ईवीएम प्रदर्शन वैन पहुंचा।

मतदान केन्द्र में ईवीएम, वीवीपैड का प्रर्दशन किया गया और वहां के मतदाताओं को इसके बारे में जानकारी दी गई। मतदाताओं ने ईवीएम व वीवीपैड मशीनों में हैड्स ऑन भी किया। अब तक जिले के 64 मतदान केन्द्रों में 1 हजार 3 लोगों ने हैड्स ऑन किया है। कलेक्टर महोबे के मार्गदर्शन में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जिला कार्यालय परिसर में ईवीएम प्रदर्शन केंद्र बनाया गया है। ईवीएम प्रदर्शन केंद्र में जिले के नागरिक ईवीएम, वीवीपैड के सबंध में जानकारी ले सकते है और इसमें हैंड्स ऑन भी कर सकते है। साथ ही दोनों विधानसभा के रिटर्निंग ऑफ्सिर 71-पंडरिया और 72-कवर्धा के कार्यालय में भी ईवीएम प्रदर्शन केंद्र बताया गया है।

जिले के दोनों विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र 71-पंडरिया और 72-कवर्धा के मतदान केन्द्रों में ईवीएम प्रदर्शन वैन को सभी मतदान केन्द्रों में ईवीएम, वीवीपैड जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन और प्रशिक्षण, हैंड्स ऑन कराया जा रहा है। यह कार्यक्रम लगभग 3 महीने तक चलेगा।

मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना से संवर रहे जिले के स्कूल

श्रीकंचनपथ न्यूज

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत अब जिले के स्कूल संवरने लगे हैं। जिले में योजना अंतर्गत शाला भवन मरम्मत नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्य के साथ अतिरिक्त कक्ष निर्माण कराया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत प्राथमिक शाला देवरीबाहरा, शासकीय पूर्व प्राथमिक शाला भवन सोहागपुर और पारागांव के स्कूल भवन का जीर्णोद्धार कार्य किया गया है।

जिसमें प्राथमिक शाला देवरीबहरा का 4 लाख 56 हजार रूपये की लागत से उन्नयन कार्य किया गया। पूर्व में इस भवन के छत में सीपेज की समस्या थी, जिसमें कंक्रीट वाटर प्रूफिंग ग्रेंडिंग का कार्य किया गया। साथ ही फर्श में टाइल्स, विद्युतीकरण कार्य, पोताई, पेंटिंग कार्य किया गया। इसी प्रकार मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत माध्यमिक शाला भवन सोहागपुर के लिए 4 लाख 23 हजार रूपये की लागत से जीर्णोद्धार का कार्य किया गया। इस स्कूल भवन में फर्श टूट गया था तथा बरसात के समय छत से पानी टपकने की समस्या थी। जिसे फर्श में टाइल्स का कार्य, छत में कंक्रीट ग्रेडिंग कार्य, दरवाजा मरम्मत एवं पुट्टी-पोताई का कार्य किया गया और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पारागांव में छत की स्थिति पूर्व में बहुत खराब थी। इस स्कूल भवन में 4 लाख 56 हजार रूपये की लागत से कंक्रीट ग्रेडिंग वाटर प्रूफिंग कम्पाउंड का कार्य किये जाने से छत से पानी टपकने की समस्या ठीक हो गया।

फर्श पूरी तरह से खराब हो गया था, जिसमें नया फर्श लगाने का कार्य कराया गया है तथा छात्रों के लिए पानी टंकी एवं हाथ धुलाई के लिये प्लेटफार्म व नल फिटिंग की व्यवस्था की गई है। स्कूल भवन में पोताई, पेंटिंग व विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना से जीर्णोद्धार से नये भवन मिल जाने से सभी बच्चे खुश हैं।

ऑल इंडिया लघु एवं मध्यम समाचार पत्र फेडरेशन के राष्ट्रीय सम्मेलन में वर्चुअली शामिल हुए राज्यपाल

समाज में बदलाव लाने में समाचार पत्रों की महती भूमिका

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज भुवनेश्वर में आयोजित ऑल इंडिया लघु एवं मध्यम समाचार पत्र फेडरेशन के राष्ट्रीय सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव लाने के लिए समाचार पत्रों की महती भूमिका है।

राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लघु समाचार पत्रों का योगदान भुलाया नही जा सकता। आजादी के लिए जागरूकता और उत्साह भरने और एकजुट होकर लड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन लघु समाचार पत्र ने किया।

महात्मा गांधी जी द्वारा संपादित ''हरिजन'' पत्रिका ने स्वदेशी आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने में विशेष भूमिका निभाई। यंग इंडिया जैसी पत्रिकाएं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के विरूद्ध लड़ाई के साथ-साथ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम करती थीं। राज्यपाल ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में प्रेस की महती भूमिका है। संविधान में सभी को समान अधिकार प्राप्त है। सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। लोगों को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब लोगों के मुलभूत अधिकारों का हनन होता है तो शोषण के खिलाफ लड़ने और लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

राज्यपाल ने कहा कि यह सम्मेलन समाचार पत्रों के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका धारको को और पत्रकारों के बीच ज्ञान विनिमय के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। उन्होंने आग्रह किया कि इस सम्मेलन में देश की समस्याओं पर भी चर्चा करें। अपने समाचार पत्रों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रीत करें और समाज में बदलाव लाने के लिए सक्रिय रहें। समाज मे व्याप्त विषमता, भ्रष्टाचार, शोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों पर अपने लेखो के माध्यम से चर्चा करें और लोगों को समाधान के लिए प्रेरित करें।

इस अवसर पर फेडरेशन के पदाधिकारी एवं देश भर से आये हुए विभिन्न लघु एवं मध्यम समाचार पत्र संस्थाओं के मालिक संपादक, और प्रकाशक उपस्थित थे। राज्यपाल ने फेडरेशन द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया।

रमन सरकार ने छत्तीसगढ़ में शराब की खपत को बढ़ाया था कांग्रेस राज में कम हुआ-कांग्रेस

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। कांग्रेस की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में शराब की खपत में कमी आई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सरकार ने छत्तीसगढ़ में शराब का सरकारीकरण कर प्रदेश में शराब की खपत को बढ़ावा दिया। भाजपा सरकार का उद्देश्य शराब से राजस्व को बढ़ाकर ज्यादा मुनाफ कमाना था। रमन राज छत्तीसगढ़ प्रति व्यक्ति शराब की खपत में गोवा के बाद पहले नंबर पर था, कांग्रेस सरकार के पांच सालों में प्रति व्यक्ति शराब की खपत में छत्तीसगढ़ 18वें नंबर पर आ गया है।

राज्य में शराब की खपत कम करने कांग्रेस सरकार ने 100 से अधिक शराब दुकानों को बंद किया। आज छत्तीसगढ़ में 2018 की अपेक्षा अंग्रेजी शराब की खपत में 15 फीसदी और देशी शराब की खपत में 10 प्रतिशत की कमी आई है।

रमन सिंह से कांग्रेस के सवाल-

1. शराब का सरकारीकरण क्यों किया था? आखिर वह कौन से कारण थे जिसके चलते शराब बिक्री का व्यवसाय निजी हाथों से छीनकर सरकारी हाथों में लेना पड़ा?
2. रमन राज के 15 साल में प्रदेश में शराब की दुकानों की संख्या में 40 प्रतिशत की

बढ़ोत्तरी क्यों हुई थी? शराब की दुकाने ज्यादा खोलने के पीछे का आपका मकसद क्या था?

3. 2017 में यह बयान था कि भले चुनाव हार जाऊं लेकिन शराब बंदी लागू करूंगा, फिर क्यों शराब बंदी नहीं लागू किया था?
4. रमन सिंह के सरकार में होटल, बार में शराब परोसने के लिये बच्चियों, बेटियों को ट्रेनिंग क्यों दी जा रही थी?
5. छत्तीसगढ़ की शराब नीति में बदलाव क्यों किया था? इससे किसको फायदा पहुंचा था?
6. क्या यह सच नहीं है कि रमन सिंह ही के शासनकाल में शराब से मिलने वाला राजस्व 400 करोड़ रूपए से बढ़ते-बढ़ते 5000 करोड़ के आसपास पहुंच गया था? शराब बिक्री की इस अप्रत्याशित वृद्धि की वजह क्या थी?
7. प्रदेश की जनता यह भी जानना चाहती है कि रमन सरकार में शराब बिक्री के सरकारीकरण होते ही बियर का एक विशेष ब्रांड ही हर दुकान में क्यों बिकता था और उस ब्रांड का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ क्या संबंध है?
8. 4400 करोड़ के शराब घोटाला के बारे में कोई जवाब क्यों नहीं देते?
9. एक ही अधिकारी को संविदा बढ़ाकर 9 साल तक शराब के कारोबार का जिम्मा क्यों देकर रखा था?
10. रमन मंत्रिमंडल की बैठक में आपके सहयोगी मंत्री प्रेमप्रकाश पांडे ने कहा था शराब की कमीशन के हर साल मिलने वाला 1500 करोड़ किसके पास जायेगा? रमन सिंह जी बताईये यह 1500 करोड़ की रकम प्रतिवर्ष किसकी जेब में गयी?

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ को शराब मुक्त करने के लिये प्रतिबद्ध। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा चलाये जा रहे जनजागरण और शराब की खपत को हतोत्साहित करने का परिणाम है कि जो छत्तीसगढ़ रमन राज में प्रति व्यक्ति शराब की खपत में गोवा के बाद पहले नंबर पर था वह अब 18वें नंबर पर है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हम छत्तीसगढ़ में नोटबंदी के समान शराब बंदी नहीं लागू करेंगे ताकि इसके दुष्परिणाम सामने आये। इसके लिये जनजागरण चलाकर लोगों की शराब की लत छुड़वा कर शराब बंदी लागू की जायेगी ताकि 7 राज्यों से घिरे छत्तीसगढ़ में शराब बंदी एक अभिशाप के रूप में सामने न आये।

ग्राम भटगांव निवासी ने प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

गरियाबंद। ग्राम भटगांव की आवास हीन ब्यक्ति नियान सिंह ने गरियाबंद सँयुक्त कार्यालय पहुच कर आवास की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौपा।वही ज्ञापन में उक्त ब्यक्ति ने उल्लेख करते हुए बताए कि गत वर्ष माह अगस्त में कृष्ण केजन्माष्टमी के दिन 18 जुलाई को भारी बारिश के दौरान उनका मकान क्षतिग्रस्त होकर ढह गया।उस घटना की सूचना ग्राम समूह के सदस्यों और ग्रामपंचायत को लिखित में ढिया गया है। चुकी उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मकान नही बना पाए,जिससे उक्त ब्यक्ति परिवार सहित ग्राम समिति से अनुरोध कर सामुदायिक भवन में निवासरत है। प्रधानमंत्री आवास दिलाने की मांग किये।

ॐ साई राम
माँ पुस्तक भंडार
होलसेल में कापी-किताब एवं स्टेशनरी सामान मिलने का एक मात्र स्थान
पुरानी एवं नई पुस्तकें खरीदी व बेची जाती है
रावणभाटा, सुपेला, भिलाई (छ.ग.)
मो. 7489051024, 7770845578

Since 1972
CROWN® - TV
Choice Of Millions
LED Available 16 -20 -22 - 24 - 32-40-50-55-65

CONTACT
Premier sales 8959493000
Arhum Electronics 9926100315
A Leela Electronics 9425507772
Reena Electronics 9329132299
Shree Electronics 7000827361
Maa Durga Electronics 9827183839
Rohit Electronics 94242-02866
Authorised Distributers For Chhattisgarh
Trade Enquiry: 98262-52372

खास खबर...

भाजयुमो का व्यापम घेराव राजनितिक नौटंकीः कांग्रेस

रायपुर (ए)। भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी अपना अनुभव बता रहे है। रमन सरकार के दौरान ओपी चौधरी कलेक्टर की नौकरी छोड़ कर भागे थे इससे ही समझ में आता है कि उस दौरान अधिकारियों के ऊपर कितना अनैतिक दबाव रहा होगा। चौधरी जैसे कई अधिकारियों ने रमन भाजपा सरकार के दबाव में नौकरी से त्यागपत्र दिया था कुछ अधिकारी कर्मचारी विवश होकर आत्मघाती कदम उठाये थे। बिलासपुर एसपी राहुल शर्मा की आत्महत्या की घटना प्रदेश भुला नही है।

प्रदेश प्रवक्ता ठाकुर ने कहा कि यूपीएससी में चयनित युवाओ का राजधानी में वर्कशॉप का आयोजन होना स्वागतयोग है। इससे नए युवाओ को जानकारी मिलेगी जनक मार्गदर्शन होगा इसे भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? असल में भाजपा छत्तीसगढ़ के हर मामले का विरोध कर अपने विपक्ष में होने का एहसास कराती है लेकिन वह भूल जाती है उनके इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन से जनता में भाजपा की छवि धूमिल होती है। पूरा प्रदेश ने देखा 15 साल के रमन सरकार के दौरान अधिकारी कर्मचारी तानाशाही के शिकार थे। किसान, शिक्षाकर्मी, नर्स, स्कूल के छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। 15 साल में सीधी भर्तियां नहीं होती थी, रमन सिंह और उनके रिश्तेदार कुछ चाटुकार अधिकारियों के चलते पूरा अधिकारी हताश परेशान थे, कलेक्टर के ऊपर 8 पास संघ के नेताओं को सलाहकार बनाकर रखा गया था।

राज्य सूचना आयोग ने दो जन सूचना अधिकारियों पर लगाया अर्थदंड

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सूचना देने में लापरवाही बरतने पर दो जन सूचना अधिकारियों पर 25- 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इन अधिकारियों में एक तत्कालीन तहसीलदार और एक तत्कालीन उप अभियंता शामिल है। राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन के निराकरण में लापरवाही बरतने और समय सीमा में क्रियान्वयन नहीं किये जाने पर संबंधित जनसूचना अधिकारियों पर यह अर्थदंड लगाया है। एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान पाया गया कि रायपुर तहसील के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी को मार्च 2019 में आवेदक द्वारा सीमांकन से संबंधित दस्तावेजों आदि का अवलोकन करने का आवेदन दिया गया था। किंतु जन सूचना अधिकारी के द्वारा 3 वर्ष विलंब से आवेदक को अवलोकन के लिए सूचना जारी किया गया। इस संबंध में आयोग के द्वारा तत्कालीन जन सूचना अधिकारी को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया, जिसका कोई जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया। इस कारण से तत्कालीन जन सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रायपुर एवं वर्तमान में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर अमित बेक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

पीसीपीएनडीटी एक्ट के राज्य सलाहकार समिति की हुई बैठक

रायपुर। पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत गठित राज्य सलाहकार समिति की बैठक आज डीकेएस भवन परिसर स्थित राज्य नोडल एजेंसी कार्यालय में हुई। पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में स्त्री रोग विभागाध्यक्ष डॉ. ज्योति जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य में इस एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के परिपालन पर चर्चा हुई। राज्य सलाहकार समिति की बैठक में सोनोग्राफी मशीन में एक्टिव ट्रेकर लगाने संबंधी भारत सरकार से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत एमबीबीएस डॉक्टरों के सोनोग्राफी प्रशिक्षण के अगले बैच के लिए नियमावली तैयार करने पर भी चर्चा की गई। विगत 31 मार्च को हुई समिति की पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन की जानकारी भी बैठक में दी गई। पीसीपीएनडीटी एक्ट के संयुक्त संचालक डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव, पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में रेडियो डायग्नोसिस के प्राध्यापक डॉ. विवेक पात्रे, शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉ. ओंकार प्रसाद खंडवाल, मेडिसीन विभाग के सह-प्राध्यापक डॉ. आर.के. पटेल, स्वास्थ्य विभाग के उप संचालक डॉ. महेन्द्र सिंह, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धवल सिन्हा और पीसीपीएनडीटी कन्सल्टेंट सुश्री वर्षा राजपूत भी बैठक में उपस्थित थीं।

यूपीएससी 2022 के टॉपर्स ने की टॉपर्स टॉक बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के प्रतियोगी रहे मौजूद

छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित करना लक्ष्यः कलेक्टर डॉ. भुरे

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए आज का दिन विशेष रहा। आज स्थानीय प्रतिभागियों को देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी के वर्ष 2022 के टॉपर्स से मिलने और उनसे परीक्षा के बारे में जानने का अवसर मिला। जिला प्रशासन द्वारा आज राजधानी रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में टॉपर्स टॉक का आयोजन किया गया।

इस टॉक में सिविल सेवा परीक्षा की टॉपर इशिता किशोर के साथ सेकेण्ड टॉपर गरिमा लोहिया और नौवां स्थान प्राप्त करने वाली कनिका गोयल 17वीं रैंक पाने वाले अविनाश कुमार, छत्तीसगढ से सर्वोच्च रैंक पाने वाले अभिषेक चतुर्वेदी और 2021 की परीक्षा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित प्रखर चंद्राकर ने प्रतिभागियों को परीक्षा के बारे में अपने अनुभव बताये। टॉपर्स ने यूपीएससी परीक्षा के बारे में परीक्षार्थियों को पूरी जानकारी देने के साथ उनके सवालों का समाधान भी किया।

बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के प्रतियोगी रहे मौजूद

टॉपर्स टॉक के लिए सुबह से ही दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम में छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों की भीड़ जुटने लगी थी। रायपुर ही नहीं आसपास के दूसरे जिलों से भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा टॉपर्स को सुनने और उनके टिप्स लेने बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक के लाइव लिंक के जरिये भी करीब 8 हजार प्रतिभागियों ने ऑनलाईन इस टॉपर्स टॉक का सीधा प्रसारण देखा और टॉपर्स के अनुभवों से रूबरू हुए।

यूपीएससी टॉपर्स को राजकीय गमछा तथा प्रतीक चिन्ह से किया गया सम्मानित

टॉपर्स टॉक समारोह में छत्तीसगढ़ की सभ्यता एवं संस्कृति से रूबरू कराते हुए रायपुर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल नगर निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी, जिला पंचायत सीईओ अबिनाश मिश्रा तथा सहायक कलेक्टर जयंत नहाटा ने यूपीएससी टॉपर्स को राजकीय गमछा तथा वनभैंसा का प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया।

छत्तीसगढ़ के राजगीत के साथ शुरू हुई टापर्स टॉक

छत्तीसगढ़ के राजगीत अरपा पैरी की धार से टॉपर्स टॉक की शुरूआत हुई। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने इस अवसर पर कहा की इस टॉक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ से अधिक से अधिक प्रतिभागियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित करना और सफलता में अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से युवाओं में माहौल बनता है और वे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गंभीर होकर तैयारी करते है। कलेक्टर डॉ. भुरे ने सभी टॉपर्स का छत्तीसगढ़ शासन की ओर से स्वागत किया।

एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि इन टॉपर्स से छत्तीसगढ़ के युवाओं को अच्छी जानकारी मिलेगी। उन्होंने इस परीक्षा के लिए लगन और समर्पण को जरूरी बताया। एसएसपी ने कहा कि यूपीएससी की परीक्षा के लिए विस्तृत सिलेबस को जानना और दृढ़ निश्चय बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। एसएसपी ने नकारात्मक बातों और लोगो से बचने और अनुशासन के साथ पढ़ाई कर तैयारी करने की सलाह प्रतिभागियों को दी।

प्रशिक्षणार्थियों ने दैनिक जीवन में योग के प्रभाव और फायदों को जाना

योग आयोग द्वारा सात दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा रायपुर के वीआईपी रोड फुण्डहर स्थित योग भवन में आयोजित योग प्रशिक्षण शिविर में योग प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा दैनिक जीवन में योग के प्रभाव और फायदों के संबंधों में बताया जा रहा है। शिविर में प्रशिक्षणार्थियों को डॉ. दिनेश नाग ने योग के साथ आयुर्वेद के संबंध व प्रभाव के बारे में बताया और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. आशा जैन ने प्रसव के दौरान योग की भूमिका विषय पर विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही लच्छू राम निषाद ने यम, प्रत्याहार, धारणा पर प्रकाश डाला, सीएल सोनवानी ने षटकर्म के बारे में बताया। इस अवसर पर योग आयोग के सचिव एमएल पाण्डेय सहित योग प्रशिक्षकगण उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि रायपुर, बिलासपुर एवं बस्तर संभाग के सफल आयोजन के बाद सरगुजा संभाग के प्रशिक्षणार्थियों के लिए सात दिवसीय आवासीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सरगुजा संभाग के सभी जिलों से लगभग 130 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ 15 जुलाई को शंकराचार्य आश्रम बोरियाकला के मुख्य पुजारी इंदुभवानंद महाराज के मुख्य आतिथ्य और छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन के लिए नियमित योग करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है।

वन्य प्राणियों के भोजन तथा रहवास सुधार में चारागाह विकास काफी उपयोगीः वन मंत्री अकबर

नरवा विकासः वनांचल के लगभग 5 हजार हेक्टेयर भूमि में हो रहा चारागाह विकास

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नरवा विकास कार्यक्रम के तहत वनांचल स्थित नालों में काफी तादाद में भू-जल संवर्धन संबंधी कार्य कराए जा रहे है। इसके अंतर्गत कैम्पा मद की वार्षिक कार्य योजना 2022-23 में 11 करोड़ 79 लाख रूपए की स्वीकृत राशि से वन क्षेत्रों के 4 हजार 751 हेक्टेयर क्षेत्र में चारागाह विकास का कार्य प्रगति पर है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसे वन्य प्राणियों के भोजन तथा रहवास सुधार के लिए काफी उपयोगी बताया है। गौरतलब है कि वर्ष 2022-23 में ही छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण, निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण ''कैम्पा'' की वार्षिक कार्य योजना के तहत 1 हजार 503 नालों का चयन कर 6 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि का उपचार जारी है। इनमें 29 लाख से अधिक भू-जल संबंधी संरचनाओं का निमार्ण किया जा रहा है। इनके निमार्ण के लिए प्रदेश के 32 वनमंडल, 2 राष्ट्रीय उद्यान, 3 टाइगर रिजर्व तथा 1 ऐलीफेंट रिजर्व में 300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत है। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक व्ही. श्रीनिवास राव ने बताया कि कैम्पा के तहत वर्ष 2022-23 में प्रदेश के वनांचल स्थित 239 स्थलों का चयन चारागाह विकास के लिए किया गया है। इनमें सर्वाधिक 85 स्थलों का चयन वन्य प्राणी संरक्षण के अंतर्गत किया गया है। यहां स्वीकृत 4 करोड़ 93 लाख रूपए की राशि से 1 हजार 955 हेक्टेयर भूमि में चारागाह विकास किया जा रहा है। इसी तरह सरगुजा वनवृत्त अंतर्गत चारागाह विकास के लिए 62 स्थलों का चयन किया गया है। यहां 2 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि से 1 हजार 120 हेक्टेयर भूमि में कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा बिलासपुर वनवृत्त के अंतर्गत 36 स्थलों में 1 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि से 600 हेक्टेयर भूमि, कांकेर वनवृत्त अंतर्गत 22 स्थलों में 1 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि से 475 हेक्टेयर तथा दुर्ग वनवृत्त अंतर्गत 18 स्थलों में 91 लाख़ रुपए की राशि से 361 हेक्टेयर और रायपुर वनवृत्त अंतर्गत 8 स्थलों में 50 लाख़ रुपए की राशि से 200 हेक्टेयर में चारागाह विकास का कार्य जारी है।

जनसम्पर्क संचालनालय में हुई आंतरिक परिवाद समिति की बैठक

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न पर जागरूकता के संबंध में हुई चर्चा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में इन्द्रावती भवन नवा रायपुर स्थित जनसम्पर्क संचालनालय में गुरूवार को आंतरिक परिवाद समिति की बैठक आयोजित की गई। समिति की अध्यक्ष संयुक्त संचालक हर्षा पौराणिक ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे सभी कार्यालय जहां न्यूनतम 10 कर्मचारी हो, आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जा सकता है। परिवाद समिति के गठन के लिए जरूरी नहीं है कि कार्यालय में 10 महिलाएं हों। कार्यालय में काम में नियोजित दैनिक महिला कर्मचारी भी आंतरिक परिवाद समिति में लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत कर सकती है।

श्रीमती पौराणिक ने बताया कि लैंगिक उत्पीड़न में अश्लील साहित्य दिखाना, टिप्पणी करना, लैंगिक प्रकृति का अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण भी शामिल है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है। बदलते समय के साथ महिलाओं में झिझक और डर कम हुआ है और महिलाएं आगे आकर अपनी बात कहने लगी हैं। उन्होंने बताया कि परिवाद समिति की जानकारी के संबंध में हर कार्यालय के बाहर बोर्ड लगाने का नियम भी लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के प्रावधानों में दिया गया है, जिससे अधिनियम और उसमें दिए गए अधिकारों के बारे में सभी महिलाओं को जानकारी हो सके।

आंतरिक परिवाद समिति की सदस्य और वरिष्ठ महिला पत्रकार सुश्री शगुफ्ता शीरीन ने कहा कि लैंगिक उत्पीड़न के प्रावधानों के संबंध में महिलाओ में जागरूकता की जरूरत है। समिति में की गई शिकायत गोपनीय रहती है। महिलाओं को बिना शर्म और डर के अपनी बात समिति में रखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह अधिनियम बनाया गया है, उन्हें इसके दुरूपयोग से बचना चाहिए। बैठक में उप संचालक नीलिमा अग्रवाल, सहायक संचालक तौकीर जाहिद, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी सुश्री रीनू ठाकुर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर प्रतिभा पांडेय सहित संचालनालय की अन्य महिला कर्मचारीगण उपस्थित थीं।

नंदनी रोड, लिंक रोड, सर्कुलर मार्केट, जवाहर मार्केट पावर हाउस, भिलाई के प्रतिष्ठित संस्थान विज्ञापन के लिए संपर्क करें:-
9303289950, 9827806026, 8962815243

जैकलीन फर्नांडिस के फोटोशूट ने इंस्टाग्राम पर लगाई आग

बॉलीवुड फिल्मों की जानी मानी मशहूर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस इंडस्ट्री की जान मानी एक्ट्रेस हैं। अपने करियर में जैकलीन ने कई हिट फिल्में दी हैं। पिछले दिनों अभिनेत्री का नाम सुकेश चंद्रशेखर के साथ जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर खूब खबरों में रहा था। सुकेश संग नाम जुड़ने के पश्चात् सोशल मीडिया पर जैकलीन को जमकर ट्रोल भी किया गया। वहीं, अब जैकलीन की लेटेस्ट बोल्ड फोटोज सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इन फोटोज में उनका सुपर बोल्ड अवतार देखकर प्रशंसकों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इन फोटोज को देखने से पहले आप भी अपना दिल थाम लें।

जैकलीन फर्नांडिस अभिनय के साथ सोशल मीडिया पर भी जमकर एक्टिव रहती हैं। हाल ही में जैकलीन ने अपना बोल्ड फोटोशूट कराया है, जिनकी फोटोज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की हैं। इन फोटोज में उनकी हॉटनेस बस देखते ही बन रही है। फोटोज में आप देख सकते हैं कि जैकलीन ने ब्लैक कलर का डिजाइन ब्रालेट पहना हुआ है। फ्रंट से इस ब्रालेट का डिजाइन बहुत यूनिक है। इसके साथ उन्होंने ब्लू डेनिम जींस कैरी की है। वहीं, अपने लुक को और भी खूबसूरत बनाने के लिए जैकलीन फर्नांडिस ने अपने बालों को खुला रखा है।

इन फोटोज में जैकलीन फर्नांडिस अलग-अलग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। इस फोटो में उनका जलवा बस देखते ही बन रहा है। जैकलीन फर्नांडिस की ये तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं। इन पर कमेंट कर यूजर्स निरंतर प्रतिक्रिया देते दिखाई दे रहे हैं। इस पर कमेंट कर एक शख्स ने जैकलीन को ट्रोल करते हुए लिखा, वो जो सुकेश है उस पर डॉक्यूमेंट्री मूवी बनने वाली है, तो आप अपने किरदार में किसको देखना चाहती है। इसी तरह कई लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए है।

प्रेग्नेंसी में पैरासिटामोल खाना सही या नहीं? पेट में पल रहे बच्चे पर इसका क्या होता है असर

जब किसी को बुखार होता है तो वह अपने और भी कई तरह की बीमारी लेकर आती है। जैसे सिर दर्द, शरीर में दर्द आदि। बुखार को ठीक करने के लिए अक्सर हम क्रोसिन, पैरासिटामोल, डोला, सुमो, कालपोल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या प्रेग्नेंसी के दौरान भी इन दवाईयों का इस्तेमाल कर सतते हैं। कहीं यह बच्चे के लिए खतरनाक तो साबित नहीं होगा। प्रेग्नेंसी के दौरान कुछ महिलाएं तो बिना डॉक्टर से पूछे दवा नहीं खाती हैं लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो बिना सोचे समझे धड़ल्ले से पैरासिटामोल खा लेती हैं। आज हम आपको अपने आर्टिकल के जरिए यह बताने की कोशिश करेंगे कि प्रेग्नेंसी में पैरासिटामोल खाना सही है या नहीं?

पैरासिटामोल खाने से बच्चे के शरीर पर पड़ता है ऐसा असर

रिसर्च के मुताबिक प्रेग्नेंसी के दौरान पैरासिटामोल इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह प्लेसेंटा के बैरियर को पार कर लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं यह भ्रूण को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। इसका सीधा असर बच्चे के विकास पर भी होता है। और बच्चा का लिवर भी खराब कर सकता है। पैरासिटामोल खाने से बच्चों का रिप्रोडक्टिव और यूरोजेनाइटल डिसॉर्डर का जोखिम भी बढ़ा देता है। इस बीमारी में बच्चे का पेशाब करने का रास्ता ठीक से खुलता नहीं है।

बच्चे में आईक्यू की कमी

रिपोर्ट के मुताबिक प्रेग्नेंसी के दौरान पैरासिटामोल खाने से भ्रूण पर गंभीर असर पड़ता है। हालांकि इस पूरे रिसर्च में यह कहीं भी नहीं मिला कि पैरासिटामोल खाने वाली महिला का बच्चा प्रसव से पहले हो जाता है। लेकिन कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रेग्नेंसी में पैरासिटामोल खाना चाहिए या नहीं इसे लेकर अब तक कई रिसर्च हो चुकी है। डेली मेल में छपी खबरे क मुताबिक प्रेग्नेंसी के दौरान ज्यादा पैरासिटामोल का इस्तेमाल आपके भ्रूण के लिए कई तरह की मुश्किलें हो सकती है। रिसर्च के मुताबिक ज्यादा पैरासिटामोल के इस्तेमाल से बच्चे में अटेंसन डेफीसिट हाइपरएक्टिविटी डिसॉडर, ऑटिज्म, लैंग्वेज और आईक्यू की दिक्कत हो सकती है।

क्या आप भी डाइजेस्टिव बिस्किट्स को हेल्दी समझ कर खाते हैं?

ये 5 गंभीर नुकसान हो सकते हैं

हम भारतीयों को चाय बिस्किट खाना काफी पसंद है। मार्केट में एक से बढ़कर एक बिस्किट मौजूद है। हालांकि ये बिस्किट सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होते। यही वजह है कि लोग डाइजेस्टिव बिस्किट खाना ज्यादा प्रिफर करते हैं। बिस्किट बनाने वाली भी कंपनियां दावा करती है कि डाइजेस्टिव बिस्किट में मैदा नहीं होता। ये आसानी से पच जाता है। कई बार जो लोग बीमार रहते हैं वह भी डाइजेस्टिव बिस्किट खाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि डाइजेस्टिव बिस्किट भी हेल्दी नहीं है। इसे खाने से आपके सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से।

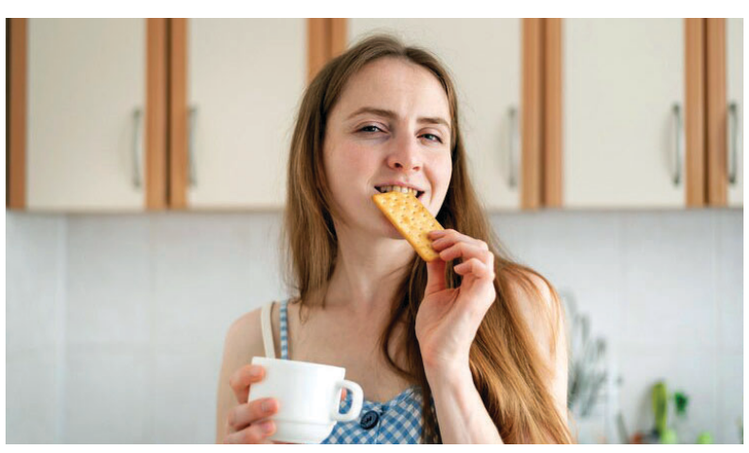

क्या सच में अनहेल्दी है डाइजेस्टिव बिस्किट

जिस डाइजेस्टिव बिस्किट को आप हेल्दी समझकर महंगे दामों पर खरीदते हैं उन्हें बनाने के लिए कई तरह के केमिकल और प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप लगातार इस तरह के बिस्किट का सेवन करते हैं तो इससे आपकी सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, रिफाइंड आटे का इस्तेमाल किया जाता है। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए टेस्ट इन्हेंसर का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि सेहत के लिए काफी नुकसानदायक होता है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर आप डाइजेस्टिव बिस्किट का सेवन करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि इसमें कम चीनी होती है लेकिन इन्हें ऐसा स्वाद लाने के लिए नेचुरल यानी प्राकृतिक के स्विटर के साथ ही अलग से चीनी का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करने से यह हेल्दी डाइट ना रहकर आपकी डाइट में एक्स्ट्रा चीनी ऐड करने का काम कर देते हैं। इनके बहुत अधिक सेवन से दांतों का खराब होना, मोटापा, दिल से जुड़ी बीमारियों या डायबिटीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

डाइजेस्टिव बिस्किट खाने के नुकसान

- डाइजेस्टिव बिस्किट में सैचुरेटेड फैट की मात्रा होती है जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना हो सकती है।
- डाइजेस्टिव बिस्किट को बनाने में सोडियम का भी इस्तेमाल होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में इनका सेवन हाई बीपी से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। जिससे आपके दिल को भी नुकसान हो सकता है।
- डाइजेस्टिव बिस्किट को बनाने में भी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें सुगंध के लिए भी कई तरह के एसेंस मिलाए जाते हैं। जिस से भी आप को गंभीर नुकसान हो सकता है।
- बिस्किट को बनाने में आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल किया जाता है।इससे ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा हो जाता है।
- डाइजेस्टिव बिस्किट में मैदे की ज्यादा गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। गेहूं के आटे में ग्लूटेन होता है। अलग अलग ब्रांड की डाइजेस्टिव बिस्किट में ग्लूटेन की मात्रा अलग-अलग इस्तेमाल की जाती है अगर आप ग्लूटेन सेंसिटिव है तो यह डाइजेस्टिव बिस्किट आपके लिए सेहतमंद नहीं हो सकता है। इसे आप को डायरिया, पेट दर्द की शिकायत हो सकती है।

सेक्स और लस्ट पर खुलकर बातचीत करना जरूरीः मृणाल ठाकुर

एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर, जिन्हें स्ट्रीमिंग एंथोलॉजी लस्ट स्टोरीज 2' में अपने शानदार परफॉर्मेंस के चलते काफी सराहना मिल रही है, का मानना है कि सेक्स और लस्ट पर खुलकर बात करना सबसे महत्वपूर्ण है।

लस्ट स्टोरीज़ 2' सफल रिश्तों में लस्ट और सेक्स के महत्व पर प्रकाश डालती है, जिसमें मृणाल की ऑन-स्क्रीन दादी के रूप में नीना गुप्ता का किरदार आर. बाल्की द्वारा निर्देशित फिल्म के नैरेटिव को उजागर करता है।

एक्ट्रेस ने कहा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि सेक्स और लस्ट पर खुलकर बात करना महत्वपूर्ण है, खासकर जब कोई उम्र में बड़ा हो रहा हो। जब कोई युवा वयस्क होता है, तो उसके पास एक आदर्श होता है जो एक युवा व्यक्ति को सही ज्ञान और जानकारी प्रदान करता है।

उन्होंने आगे कहा, अगर परिवार के बच्चों सहित सभी युवा के पास कम से कम एक व्यक्ति हो, जिसके साथ वे इन विषयों पर ईमानदारी से चर्चा कर सकें, तो उन्हें बाहरी दुनिया से बहुत सारी गलत जानकारी प्राप्त करने की संभावना कम होगी।

लस्ट स्टोरीज़ 2' में मृणाल ठाकुर ने जल्द ही शादी करने वाली एक महिला का किरदार निभाया है, जो अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ कथित लस्ट कोशिएंट के बारे में अपनी दादी से मजाकिया तरीके से बात करती है। लस्ट स्टोरीज़ 2' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।

सनी देओल की गदर 2 का मोशन पोस्टर जारी, उत्कर्ष शर्मा की दिखी झलक

सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर 2 का खुमार दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। यह फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी। गदर 2 साल 2001 में आई फिल्म गदर का सीक्वल है। अब निर्माओं ने 21 जुलाई (शुक्रवार) को गदर 2 का मोशन पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें सनी (तारा सिंह) अभिनेता उत्कर्ष शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, गदर 2 का ट्रेलर 25 जुलाई को जारी किया जाएगा।

सनी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर गदर 2 का मोशन पोस्टर साझा किया है। उन्होंने लिखा, अपने देश और परिवार की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है तारा सिंह। गदर 2 आ रही है पर्दे पर स्वतंत्रता दिवस पर। सिनेमाघरों में 11 अगस्त से। गदर 2 की कहानी 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर आधारित होगी, जिसे पहले भाग के खत्म होने के 17 साल बाद सेट किया गया है।

मोशन पोस्टर की शुरुआत में एक संदेश लिखा आता है, एक पिता का प्यार किसी बंधन को नहीं मानता। फोटो में सनी देओल एक्टर उत्कर्ष शर्मा का हाथ पकड़कर भागते नजर आ रहे हैं। रेतीले रास्ते में पत्थर भी खूब हैं। सनी देओल के तीखे तेवर देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म में भी वह पड़ोसी मुल्क के छक्के छुड़ाते नजर आएंगे।

गदर 2 की कहानी पिछले फिल्म के आगे की कहानी होगी। इसमें उत्कर्ष शर्मा फिल्म की कमान संभालते नजर आएंगे।

पहली फिल्म गदर-एक प्रेम कथा को 15 जून 2001 में रिलीज किया गया था। 190 मिलियन के बजट में तैयार की गई इस फिल्म ने 1.33 बिलियन रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था।

कल्कि 2898 एडी रखा गया प्रोजेक्ट के का नाम भगवान विष्णु बने प्रभास और योद्धा बनीं दीपिका

प्रभास और दीपिका पादुकोण की फिल्म प्रोजेक्ट के खूब सुर्खियों में है। यह फिल्म कई मायनों में खास है। एक तो इसके जरिए दीपिका पादुकोण और प्रभास की जोड़ी पहली बार दर्शकों के बीच आ रही है, वहीं इसके लिए दीपिका और अमिताभ बच्चन फिर साथ आए हैं, जो पहले पीकू में काम कर चुके हैं। सैन डिएगो में चल रहे कॉमिक-कॉन इवेंट में इस फिल्म का नाम और टीजर जारी होने से कई अहम जानकारियों से पर्दा उठ गया।

प्रोजेक्ट के का नाम कल्कि 2898 एडी रखा गया है। इसका पहला टीजर रिलीज किया गया है, जिसे निर्माताओं ने साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। कल्कि 2898 एडी की पहली झलक देख पता चलता है कि इस फिल्म को देख दर्शकों को पहले कभी न देखा गया अनुभव महसूस होगा। दीपिका जहां इसमें योद्धा की तरह लड़ रही हैं, वहीं बुराई के खिलाफ लड़ता प्रभास का किरदार भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि से प्रेरित है।

जब दुनिया में अंधकार छा जाएगा तो एक शक्ति का उदय होगा, टीजर में यही कहा गया है। फिल्म की कहानी एक अंधेरी और विनाशकारी दुनिया के इर्द-गिर्द घूमेगी। यह अब से 800 साल बाद के भविष्य पर आधारित है। प्रभास-दीपिका अपनी दुनिया बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करते दिखेंगे। टीजर इंफिनिटी वॉर और एवेंजर्स की याद दिलाता है। कल्कि भारतीय सिनेमा के स्तर को और आगे ले जाएगी, इसकी भव्यता और बैकग्राउंड म्यूजिक देख तो यही लगता है।

पहली झलक में कमल हासन और दिशा पाटनी का किरदार नहीं दिखाया गया है, वहीं टीजर का आखिरी फ्रेम प्रभास और अमिताभ के बीच टकराव की ओर इशारा कर रहा है। अमिताभ इसमें एक अन्यायी शासक के रूप में दिख रहे हैं।

प्रोजेक्ट के की घोषणा दुनियाभर के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक सैन डिएगो कॉमिक-कॉन (एसडीसीसी) में हुई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि यहां लॉन्च होने वाली यह भारत की पहली फिल्म बन गई है। कॉमिक-कॉन की शुरुआत 1970 में हुई थी। इसका मकसद कलाकारों, लेखकों, रचनाकारों और प्रशंसकों को टीवी शो से लेकर फिल्मों और ऑनलाइन गेम्स से लेकर कॉमिक्स तक, हर चीज पर चर्चा करने के लिए एक ही छत के नीचे लाना है।

दुर्ग, सुपेला और कोहका प्रतिष्ठित संस्थान विज्ञापन के लिए संपर्क करें:-
9303289950, 9827806026, 8962815243

Paul Sir
BANK P.O. & CLERK, MBA, RLY., SSC.
रामा कोचिंग
135,NEW CIVIC CENTER, Bhilai Ph. 0788-6560005

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता

बेन्टेक्स एवं ग्रहरत्न उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

खास खबर

शतरंज में छत्तीसगढ़ का नाम विश्व पटल पर अंकित करने वाले विनोद राठी का किया गया सम्मान

दुर्ग। जिला शतरंज संघ द्वारा गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया। इस अवसर पर दुर्ग प्रवास पर आए छत्तीसगढ़ शतरंज के भीष्म पितामह तथा शतरंज में छत्तीसगढ़ का नाम विश्व पटल पर अंकित करने वाले विनोद राठी का स्वागत व सम्मान एक सादे समारोह में किया गया। इस अवसर पर विनोद राठी ने अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शतरंज को बढ़ावा देने हेतु आयोजन के माध्यम से जिला संघ अपनी महती भूमिका निभाये तथा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की महत्वपूर्ण योजना चैस इन स्कूल को भी प्राथमिकता से अमल में लाएं। ज्ञात हो कि श्री राठी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में वर्ष 2002 एवं 2022 में मुख्यमंत्री ट्रॉफी अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट का सफ्ल आयोजन किया जा चुका है। वे भारतीय टीम के भी कोच रह चुके हैं। जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष ईश्वर सिंह राजपूत, कोषाध्यक्ष तुलसी सोनी, उपाध्यक्ष दिनेश जैन, एस के भगत, ललित वर्मा, मोरध्वज चंद्राकर, दिनेश नलोड़े, अजय राय सचिव मिथिलेश बंजारे, सह सचिव संजय खंडेलवाल, राकी देवांगन, दिव्यांशु उपाध्याय, हरीश सोनी एवं सदस्य राजकुमार ताम्रकार, जवाहर सिंह राजपूत, महेश दास एवं अन्य सदस्यों ने राठी जी का सम्मान किया तथा अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस की एक-दूसरे को बधाई व शुभकामनाएं दी।

कामधेनु विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

दुर्ग। दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग में संभागायुक्त एवं विश्वविद्यालय के कुलपति महादेव कावरे के मार्गदर्शन व निर्देशन एवं कुशल नेतृत्व में पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, अंजोरा के तत्वधान में बकरी पालन प्रबंधन एवं उद्यमिता विकास में 26 से 28 जुलाई 2023 तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बकरी पालन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे छत्तीसगढ़ में बकरी पालन की संभावनाएं, छत्तीसगढ़ की जलवायु के लिए उपयुक्त नस्ले, उनका आवास एवं सामान्य प्रबंधन, भोजन का प्रबंधन, बकरियों में होने वाली महत्वपूर्ण बीमारियां, उनका टीकाकरण, रोकथाम, छत्तीसगढ़ एवं भारत सरकार द्वारा बकरी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे की एन.एल.एम. एवं नाबार्ड पोषित योजनाएं, आवेदन प्रक्रिया, बैंक लोन की प्रक्रिया के बारे में विभिन्न विषय विशेषज्ञों के द्वारा सारगर्भित व्याख्यान एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। जिसके लिए प्रशिक्षण शुल्क रू. 3 हजार (बिना रहवासी) एवं रू. 4 हजार (रहवासी) रखा गया है। इस प्रशिक्षण के अधिक जानकारी के लिए प्रशिक्षण प्रभारी डॉ. रामचंद्र रामटेके सहा.प्राध्यापक एवं डॉ.एस.के.तिवारी अधिष्ठाता पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग में कार्यालयीन समय पर संपर्क किया जा सकता है।

रासायनिक खाद भण्डारण विक्रय में अनियमितता पर कार्यवाही

दुर्ग। खरीफ वर्ष 2023 में जिले में कृषि आदान सामग्री यथा-खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाई आदि का भण्डारण एवं कृषकों को वितरण कार्य प्रगतिरत है। कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा जिले में विक्रय केन्द्रों के माध्यम से कृषकों को मांग अनुसार गुणवत्तायुक्त निर्धारित दर पर कृषि आदान सामग्री की आपूर्ति हेतु निरंतर निगरानी की जा रही है। इसी कड़ी में 20 जुलाई 2023 को जिला स्तरीय निरीक्षण दल जिला उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक संचालक कृषि एस.के.कोर्राम, उर्वरक निरीक्षक वि.ख.- दुर्ग नवीन खोब्रागडे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सौरभ वर्मा एवं उर्वरक शाखा प्रभारी सह ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अनिल चन्द्राकर द्वारा संयुक्त रूप से मेसर्स कृषि विकास केन्द्र, दुर्ग के थोक एवं फुटकर विक्रय प्रतिष्ठान एवं गोदाम का निरीक्षण किया गया। उपसंचालक कृषि भगत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान के समस्त दस्तावेज स्कंध पंजी, बिल बुक, अनुज्ञप्ति पत्र, प्रतिष्ठान में विक्रय हेतु उपलब्ध कृषि आदान सामग्री आदि का अवलोकन किया गया, अवलोकन के दौरान प्रतिष्ठान में उर्वरक विक्रय हेतु पीओएस मशीन एवं भौतिक स्कंध में 475 बोरी का अंतर पाया गया, विक्रय स्थल पर खाद मूल्य सूची अद्यतन नहीं होना तथा खाद का भंडारण नियमानुसार नहीं होना पाया गया। जिस पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानों के तहत संबंधित विक्रेता को कारण बताओं सूचना जारी कर 02 दिवस का समय दिया गया है, तथा समयावधि में विक्रेता द्वारा संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानों के तहत भंडारित उर्वरक पर प्रतिबंध की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने एक अनोखा जैव विविधता संरक्षण मॉडल तैयार किया

श्रीकंचनपथ न्यूज

नई दिल्ली (पीआईबी)। केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने समग्र दृष्टिकोण से एक अनोखा जैव विविधता संरक्षण मॉडल तैयार किया है। गुजरात में द्वारका के रुक्मिणी मंदिर के पास हरियाली महोत्सव को आज संबोधित करते हुए श्री यादव ने पर्यावरण और उस पर निर्भर प्राणियों के बीच महत्वपूर्ण संतुलन के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने इस संदेश को विश्व स्तर पर फैलाने के लिए मिशन लाइफशुरू किया है।

पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला को संरक्षित करके और उसमें सबसे उपर के शिकारियों को सुरक्षित करके महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों के पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन के महत्व पर प्रकाश डाला।

उन्होंने समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और उनके संरक्षण के पारिस्थितिक संकेतक के रूप में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र और डॉल्फ़िन के महत्व पर जोर दिया। संरक्षण पहल में बहु-हितधारकों की भागीदारी को आमंत्रित करते हुए श्री यादव ने उद्योगों से हाल में शुरू की गई ग्रीन क्रेडिट प्रणाली में सक्रिय रूप से योगदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कार्बन पृथक्करण और हरित आवरण को बढ़ाने में उद्योगों की भूमिका और योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी इस संबंध में एक प्रभावी उपकरण है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि गुजरात ने मैन्ग्रोंव इकोसिस्टउम के संरक्षण के लिए पीपीपी मॉडल में असाधारण काम किया है। हालांकि, ऐतिहासिक मैंग्रोव क्षेत्रों की पहचान करने और उन्हें पुनर्स्थापित करने के प्रयासों की आवश्यकता है, जो पहले से ही खराब स्थिति में हैं।

श्री यादव ने मैन्ग्रो व वृक्षारोपण लक्ष्य, मैन्ग्रो व नर्सरियों का स्टॉक, आजीविका के अवसर, प्रचार और पहुंच कार्यक्रम के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मैन्ग्रो व क्षेत्रों में पर्यावरण-पर्यटन जैसी मुख्य गतिविधियों के महत्व पर जोर दिया ताकि मैन्ग्रोगव में 30 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करने में मदद मिल सके।

पर्यावरण मंत्री ने मैन्ग्रोधव के संरक्षण के लिए हाल ही में शुरू किए गए मिष्टी कार्यक्रम और भारत के मैंग्रोव गठबंधन का एक हिस्साव बनने के बारे में सभा को जानकारी दी। उन्होंने भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के प्रकाशन की चर्चा की जिसमें भारत में दर्ज मैन्ग्रो व की 500 प्रजातियों की शब्दावली शामिल है। गणमान्य व्यक्तियों ने मैन्ग्रौव का प्रतीकात्मक वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम के तहत वन विभाग और पहचानी गई प्रतिष्ठित कंपनियों के बीच मिष्टी (तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैन्ग्रो व पहल) के तहत समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। मैन्ग्रो व सुरक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 'वन नायकों' को भी सम्मानित किया गया।

इस कार्यक्रम में गुजरात सरकार के पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, वन और पर्यावरण मंत्री मुलुभाई बेरा, जामनगर और द्वारका की संसद सदस्य सुश्री पूनमबेन मैडम, राजकोट के विधान सभा सदस्य उदय कांगड, वन महानिदेशक चंद्र प्रकाश गोयल और एमओईएफ्औरसीसी में विशेष सचिव एस.के.चतुर्वेदी, गुजरात के पीसीसीएफ यू.डी. सिंह और गुजरात सरकार के अन्य उच्च वन अधिकारी, एन.सी.सी. और स्काउट; शारदापीठ के पंडित और भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल के प्रतिनिधियों की भी भागीदारी देखी गई।

24 से 28 तक चलेगा रोजगार मेला सप्ताह

साढ़े आठ सौ से अधिक पदों पर होगी भर्तियां

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के मार्गदर्शन में स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोडने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है। युवाओं में कौशल विकास तथा रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए इस दिशा में जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रही है। ताकि स्थानीय युवाओं को उनके योग्यतानुसार उद्योगों में अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। इसी कड़ी में आगामी 24 से 28 जुलाई तक रोजगार मेला सप्ताह का आयोजन होने जा रहा है। जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा लगभग साढ़े आठ सौ से अधिक पदों पर भर्ती की जायेगी।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार अधिकारी रामजीत राम ने बताया कि निजी क्षेत्र की रिक्तियों में प्लेसमेट को बढ़ावा देने के लिए आगामी 24 से 28 जुलाई 2023 तक रायगढ़ मितान पोर्टल में पंजीकृत आवेदकों के लिए रोजगार मेला सप्ताह का आयोजन होने जा रहा है।

अतएव पोर्टल में पंजीकृत आवेदक निर्धारित तिथि को ट्रेड के अनुसार जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायगढ़ में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते है। आवेदक रिक्तियों की विस्तृत जानकारी रोजगार मितान पोर्टल में भी अवलोकन कर सकते है।

रोजगार मेला सप्ताह के दौरान 24 से 28 जुलाई तक 30 नियोजकों के माध्यम से लगभग 856 रिक्तियां शामिल है। इनमें 24 जुलाई को 10 नियोजकों के माध्यम से कुल 139 तकनीकी रिक्तियां एवं अप्रेंटिसशिप शामिल है। जिसके लिए आईटीआई, डिप्लोमा से संबंधित शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक है। इसी तरह 25 जुलाई को 10 नियोजकों के माध्यम से 168 तकनीकी रिक्तियां एवं अप्रेंटिसशिप के लिए स्नातक, डिप्लोमा, बीई, आईटीआई जरूरी है। 26 जुलाई को 8 नियोजकों के माध्यम से 214 गैर तकनीकी रिक्तियों के लिए 12 एवं स्नातक, 27 जुलाई को एक नियोजक के माध्यम से 325 सिक्युरिटी सर्विस से संबंधित रिक्तियां शामिल है, जिसके लिए 10 वीं, 12 वीं एवं स्नातक की योग्यता जरूरी है। इसी तरह 28 जुलाई को 1 नियोजक के माध्यम से 10 रिक्तियों में डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में नि:शुल्क प्रशिक्षण स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड अप्लाइड न्यूट्रीशन रायपुर हेतु चयन किया जाएगा। इसके लिए 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

कलेक्टर ने जिले में शिक्षा गुणवत्ता के लिए शिक्षकों को किया प्रेरित

श्रीकंचनपथ न्यूज

गरियाबंद। कलेक्टर आकाश छिकारा के पहल पर जिले के शिक्षा गुणवत्ता के साथ विद्यार्थियों के परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने के लिए उत्कृष्ट गरियाबंद अभियान की शुरूआत की है। उन्होंने आज शासकीय वीर सुरेन्द्रसाय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय गरियाबंद में शिक्षकों, संस्था प्रमुखों, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयकों सहित शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों की कार्यशाला में शिक्षा गुणवत्ता पर सुधार हेतु उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिये एवं प्रेरित किया।

कलेक्टर छिकारा ने जिले के शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने, विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षाओं में शत प्रतिशत परिणाम व आवासीय कोचिंग संस्था के माध्यम से नीट, जेईई, आईआईटी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में जिले के प्रतिभावान छात्रों की सफ्लता के लिए उत्कृष्ट गरियाबंद अभियान की शुरुआत की गई है। इसी तारतम्य में जिले के विकासखंड स्तर पर संस्था प्रमुखों शिक्षकों का समन्वयक को उन्मुखीकरण करने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलेक्टर आकाश छिकारा ने आज गरियाबंद विकासखंड के शिक्षकों को प्रेरित करते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य निर्धारण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशेषकर हायर स्कूल स्तर पर यह दायित्व और बढ़ जाता है। आप सभी शिक्षक जिले में शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए कार्य करें तथा विशेष कार्य योजना बनाकर शत प्रतिशत लक्ष्य के लिए अपनी भूमिका तय करें।

जिला शिक्षा अधिकारी डीएस चौहान एवं जिला समन्वयक मिशन के एस नायक ने संकुल केंद्र प्रभारी एवं समन्वयकों को इस कार्य के लिए मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने तथा लक्ष्य केंद्रित करने के निर्देश दिए। विकासखंड शिक्षा अधिकारी आर.पी. दास तथा खण्ड स्त्रोत समन्वयक तेजेश शर्मा ने परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने के लिए शिक्षकों को अतिरिक्त प्रयास करने पर जोर दिया। इस अवसर पर अभियान के नोडल अधिकारी द्वय श्याम चंद्राकर एवं मनोज केला ने विस्तार से परियोजना के लक्ष्य एवं कार्य योजना के विभिन्न बिंदुओं पर शिक्षकों को छात्र डायरी, शिक्षक डायरी, साप्ताहिक व मासिक टेस्ट आदि के विषय पर विस्तृत जानकारी दी।

छोटे गोबरा में मलेरिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद

मलेरिया पॉजिटिव मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैनपुर में भर्ती कर किया जा रहा इलाज

श्रीकंचनपथ न्यूज

गरियाबंद। विकासखंड मैनपुर के ग्राम छोटे गोबरा में कुछ ग्रामीणों के मलेरिया पॉजिटिव पाए जाने पर मरीजों के इलाज और लोगों को मलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद है। मलेरिया के केस पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव के सभी घरों का सर्वे कर मलेरिया जांच किया गया है। साथ ही मलेरिया पॉजिटिव पाए गए मरीजों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैनपुर में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है।

इसके अलावा विभाग द्वारा गांव में डीडीटी एवं मलेरिया रोधक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। छोटे गोबरा में लगभग 485 की जनसंख्या है।

गांव के लोगों के मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी और आवश्यक दवाइयों का भी वितरण किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक 12 लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 11 प्रभावित लक्षण रहित है। सभी लोगों के बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा बेहतर

व्यवस्था सुनिश्चित की गई हैं, तथा लगातार निगरानी बनाए रखकर लोगों का इलाज और मलेरिया से बचाव के लिए जरूरी उपाय किया जा रहा है। आवश्यक दवाओं का भण्डारण ग्राम स्तर पर मितानिन के पास समुचित मात्रा में कराया गया है।

कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट पर है। कलेक्टर ने गोबरा में मलेरिया पॉजिटिव पाए गए मरीजों के बेहतर इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी लोगों के मलेरिया जांच कर मलेरिया से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने और आवश्यक दवाइयों के वितरण करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य टीम बनाकर गोबरा में मलेरिया के रोकथाम के लिए लगातार सतर्क और सक्रिय होकर काम किया जा रहा है।

कृषि क्षेत्र में जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं, उसके समाधान के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है: डॉ. हिमांशु पाठक

श्रीकंचनपथ न्यूज

नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 16-18 जुलाई 2023 तक राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, पूसा, नई दिल्ली में अपना 95वां स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस मनाया। इस अवसर पर, शानदार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और जिसने किसानों, छात्रों, उद्योग, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया है। इस प्रदर्शनी में आईसीएआर द्वारा विकसित की गई नई प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदर्शित की गई।

कार्यक्रम के दूसरे दिन, विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और कृषि, बागवानी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पशुपालन और मत्स्य पालन पर 113 आईसीएआर अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित नए नवाचारों से अवगत हुए।

डॉ. हिमांशु पाठक, सचिव (डेयर) और महानिदेशक (आईसीएआर) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए 95वें स्थापना दिवस के आयोजन के मूल उद्देश्य का वर्णन किया और बताया कि

आईसीएआर कई प्रौद्योगिकियों के निर्माण में सफ्ल रहा है जिन्हें बड़े पैमाने पर अपनाने और व्यावसायीकरण के लिए प्रसारित करने की आवश्यकता है। लाभार्थियों तक ऐसी बहुमूल्य जानकारी पहुंचाने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थापना दिवस को प्रौद्योगिकी दिवस के साथ मनाने का प्रयास किया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों, अन्य हितधारकों के बीच प्रभावशाली नवाचारों के बारे में जागरूकता फैलाना है।

खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि में नवाचारों के महत्व के बारे में रुचि और जागरूकता पैदा करने के लिए, विभिन्न स्कूलों के छात्रों को वैज्ञानिकों के साथ बातचीत के बाद प्रदर्शनी देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। कृषि शिक्षा पर अधिक ध्यान देने और कृषि में उच्च स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आईसीएआर को वैश्विक विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करने के प्रयास किए गए हैं। इससे प्रतिभावान गुणों वाले कृषि मानव संसाधनों के विकास में सहायता मिलेगी। प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर, उन किस्मों को जारी करने के अलावा जहांहमारे पास पहले से ही निर्धारित प्रणाली है, लेकिन अब आईसीएआर द्वारा विकसित कई प्रौद्योगिकियों को भी जारी करने के लिए और डेवलपर्स को उत्पादन प्रणाली, पौध संरक्षण, बागवानी के क्षेत्र में , इंजीनियरिंग, शिक्षा आदि से संबंधित मान्यता देने के लिए एक मंच मिलेगा।

डॉ. पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि आईसीएआर में विस्तार, सलाह प्रदान करने के लिए और किसानों को तकनीकी जानकारी के साथ-साथ नई प्रौद्योगिकियों के तेजी से प्रसार के लिए फ्रंटलाइन प्रदर्शन परीक्षणों का संचालन करना देश भर के 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में फैले 731 कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किया जाता है।

पेयजल सुलभता के महत्वाकांक्षी योजना के कार्यों को मिशन मोड पर करें पूर्ण : कलेक्टर

जगदलपुर। कलेक्टर विजय दयाराम के. ने गुरुवार को कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में जल जीवन मिशन के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए ग्रामीण इलाकों में पेयजल सुलभता के इस महत्वाकांक्षी योजना के कार्यों को मिशन मोड पर सर्वोच्च प्राथमिकता देकर कार्यों को पूर्ण करने कहा। उन्होंने जल जीवन मिशन के निविदाकारों द्वारा अब तक किए गए कार्यों की सराहना करते हुए शेष कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये। कलेक्टर विजय ने कहा कि शासन द्वारा लक्षित समय-सीमा में कार्य को सम्पादन करने के लिए प्रत्येक सप्ताह कार्यों की समीक्षा कर निविदा के संबंध में विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, कलेक्टर विजय ने कहा कि जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से तकनीकी मापदंडों के अनुरूप निर्धारित लक्ष्य को तय समय सीमा में हासिल करने के लिए कार्यादेश के साथ ही कार्य को शुरू करें।

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles, CPVC Pipes & Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

CAR DECOR
House Of Exclusive Seat Cover, Car Stereos Matting & Sun Control Film & Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower. Opp. Indian Coffee House, Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

ॐ SAIRAM
Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES
FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden) Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

दास गार्मेन्ट्स
जींस, शर्ट, टी-शर्ट, फ्राक सूट, फ्राक, फैंसी सलवार सूट एवं किट्स वियर,अंडर गारमेन्ट्स, गाउन के लेटेस्ट कलेक्शन
एक बार अवश्य पधारें
गणेश मार्केट, गुरुद्वारा, रोड सुपेला, भिलाई, 7828248067

Ashok
JEWELLERY
Gifts ● Toys ● Cosmetics
Perfumes ● Sia Jewellery
Beside Parakh Jewellers, Akash Ganga, Supela, Bhilai
Hello: 0788-4052727
Mukesh Jain 9009959111
Rishabh Jain 8103831329

खास-खबर

बाघ की खाल के साथ चार शिकारी हुए गिरफ्तार

कोंडागांव (ए)। जिले में करीब 20 लाख रुपए के बाघ की खाल, नाखून और दांत के साथ 4 शिकारियों को पकड़ा गया है। करीब 4 महीने पहले इन्होंने ओरछा इलाके के जंगल में तीर से बाघ का शिकार किया था। फिर खाल, नाखून और दांत निकाले और मांस को खा लिए थे। अब बेचने निकले तो पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। बाघ की उम्र करीब 3 साल थी। मामला जिले के बयानार थाना क्षेत्र का है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि टेमरू गांव के नजदीक कुछ लोग बाघ की खाल बेचने के लिए निकले हैं। ग्राहक का जुगाड़ कर रहे हैं। इसी सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जवानों को देखकर सभी युवक यहां-वहां से भागने लगे। जिसके बाद चारों को पकड़कर थाना लाया गया।

नारायणपुर जिले के हैं सभी आरोपी

आरोपियों का नाम कारूराम गोटा (28), सोनू राम (41), देउराम उसेंडी (40), लखमु ध्रुव (35) है। सभी नारायणपुर जिले के ओरछा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने पुलिस को बताया कि, गांव के जंगल में बाघ होने की खबर मिली थी। फिर उसे मारने की प्लानिंग की। जिसके बाद हरदिन बाघ को ढूंढने के लिए जंगल जाते थे। फिर एक दिन शाम के समय बाघ का शिकार किया। उस पर करीब 3 से 4 बार तीर से हमला किया गया। एक तीर पेट पर लगा। जिससे बाघ की मौत हो गई।

मंत्रालय का बड़ा अधिकारी सरपंच को किया ब्लैकमेल, यूपी से पकड़ाया शातिर बदमाश

जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले सरपंच को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। जिले के केरा गांव के सरपंच लोकेश कुमार शुक्ला को एक शख्स ने फोन किया और खुद को मंत्रालय का बड़ा अधिकारी बताते हुए ब्लैकमेल करते हुए रुपए की मांग की। इस मामले में शिकायत के बाद पुलिस एक्शन में आई और मोबाइल लोकेशन के सहारे यूपी से आरोपी को दबोच लिया गया। मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी अनुसार, नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के केरा गांव के सरपंच लोकेश कुमार शुक्ला ने बताया कि 2 जुलाई को फोन आया जिसमें आरोपी ने कहा कि मैं मंत्रालय का बड़ा अधिकारी बोल रहा हूं और तुम्हारे खिलाफ टोल फ्री नबर से 10 से 20 लोगों ने भ्रष्टाचार करने की शिकायत दर्ज कराई है। जिस पर रायपुर से जांच टीम जाएगी, अगर उन्हें गड़बड़ी मिली तो 10 से 20 लाख रु की रिकवरी भरना पड़ेगा, साथ ही आपकी सरपंची भी जाएगी। वह धमकाते हुए बोला कि आज रविवार है सब अधिकारी मंत्रालय में सीसीटीवी कैमरा बंद कर बैठे हैं, चाय पानी के लिए कुछ खर्चा करो सभी अधिकारियों ने पार्टी करने की बात कही और फोन पे पर पैसे को भेजने कहा, जब फोन पे नंबर मांगने पर फोन काट दिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएपी विजय अग्रवाल ने विशेष टीम और सायबर सेल की टीम को मोबाइल धारक आरोपी को खोजबीन के लगाया गया। इस दौरान सायबर टीम को मोबाइल लोकेशन और मुखबिर की सूचना पर उत्तर प्रदेश टीम भेजी गई। जहां आरोपी पुस्पेंद्र कुमार यादव उम्र 28 साल। निवासी खोरयान्ना थाना कटेरा झांसी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ के दौरान अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी के विरुद्ध धारा 384,419,506 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

प्रेम प्रसंग में तीसरे शख्स की एंट्री,

गला दबाकर की प्रेमिका की हत्या सुखे तालाब में दफन मिली थी लाश

श्रीकंचनपथ न्यूज

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक दिन पहले सूखे तालाब में मिली युवती की लाश का मामला सुलझ गया है। युवती की हत्या के बाद शव को दफना दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने शव बरामद करने के बाद जांच शुरू की और युवती के प्रेमी तक पहुंची। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दरअसल आरोपी मृतका का प्रेमी है और उनके बीच तीसरे शख्स की एंट्री से परेशान था और इसी वजह से उसका युवती से विवाद हुआ और इसके बाद उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।

बता दें दरिमा थाना क्षेत्र के भालूकछार गांव में गुरुवार को खेत की ओर गए ग्रामीणों ने तालाब में एक दफ्नाया गया शव देखा, जिसके पैर बाहर निकले हुए थे। सूचना पर दरिमा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। मृतका की शिनाख्त होने के बाद शव का पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में युवती की गला घोंटकर हत्या की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने आसपास पूछताछ शुरू की गई। इस दौरान पुलिस को एक अहम क्लू मिला। पुलिस को पता चला कि युवती 16 जुलाई से लापता थी।

परिजनों का बयान लेने के बाद पता चला कि युवती का भालूकछार निवासी बुंदेश्वर राम नाम के युवक प्रेम प्रसंग चल रहा था। अक्सर दोनों की बात होती और मुलाकात भी करते। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर बुंदेश्वर राम (24) को हिरासत लिया। पूछताछ में बुंदेश्वर ने सारी सच्चाई उगल दी। बुंदेश्वर राम ने पुलिस को बताया कि 16 जुलाई को युवती ने प्रेमी बुंदेश्वर राम को दरिमा मिलने के लिए बुलाया था। बुंदेश्वर राम ने उससे मिलने के बाद उसे अपनी पल्सर बाइक पर बैठाकर घर ले गया।

घर से युवती को खेत की ओर ले गया। यहां बुंदेश्वर का युवती से विवाद शुरू हो गया। दरअसल युवती एक अन्य युवक से नजदीकियां बढ़ा रही थी जो कि बुंदेश्वर को रास नहीं आया। इसी बात पर दोनों में विवाद बढ़ा। इसके बाद बुंदेश्वर ने युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसे आत्महत्या दिखाने का भी प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। इसके बाद सूखे तालाब में गड्ढा खोदकर उसमें शव को दफ्ना दिया। पुलिस ने बयान के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

छात्राओं को गर्लफ्रेंड बनने को कहता है स्कूल टीचर

आयोग तक पहुंची शिकायत, जांच हुई तो लगा शिकायतों का अंबार

श्रीकंचनपथ न्यूज

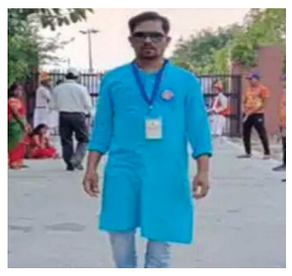

खैरागढ़। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में स्कूल टीचर पर छात्रओं ने अश्लील हरकत और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छात्राओं की यह शिकायत राज्य बाल संरक्षण आयोग तक पहुंच गई। इसके बाद आयोग की टीम ने दबिश दी जो छात्राओं ने खुलकर बयान दिया। इस दौरान 10वीं की 2 छात्राओं ने स्कूल के शिक्षक राजेश ठाकुर पर आरोप लगाते हुए कहा शिक्षक उन्हें गर्लफ्रेंड बनाने की बात करता है और साथ यह भी कहता है कि अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है।

दरअसल यह पूरा मामला खैरागढ़ ब्लॉक के भंडारपुर (करेला) हायर सेकेंडरी स्कूल की है। बाल संरक्षण आयोग की सदस्य संगीता गजभिए छात्राओं की शिकायत की जांच के लिए पहुंची। इस दौरान स्कूल के टीचर राजेश ठाकुर पर छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। राजेश ठाकुर स्कूल की छात्राओं को जीएफ बनने के लिए कहता है। इस मामले की शिकायत स्कूल स्टाफ से करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही नहीं स्कूल की कई छात्राओं ने राजेश ठाकुर पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। छात्राओं ने 19 जुलाई को इसकी लिखित शिकायत भी स्कूल प्रबंधन से की इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इधर जब आयोग की टीम पहुंची शिकायतों का पूरा पुलिंदा ही पहुंच गया। छात्राओं के आरोप के बाद टीचर ने जीएफ का अर्थ भी बदल दिया। शिकायत की जानकारी मिलने के बाद शिक्षक राजेश ठाकुर ने जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि ग्रेट फाइटर बताया। वह कह रहा था कि उसने छात्राओं को ग्रेट फाइटर बनने को कहा था। फिलहाल इस मामले को दबाने में स्कूल के स्टॉफ ने भी पूरा प्रयास किया। वहीं आयोग की टीम ने इस मामले में जब स्कूल के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कह कि 19 जुलाई को लिखित शिकायत मिलने के बाद ही उन्हें इसकी जानकारी हुई। इधर इस पूरे मामले में खैरागढ़ BEO का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि राजेश ठाकुर के मामले में प्राचार्य से थाने में FIR दर्ज कराने कहा गया है।

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर बवाल: लोगों की परेशानियों को दूर करने चर्च बुलाता है सिपाही, हिन्दू संगठनों ने की कार्रवाई की मांग

श्रीकंचनपथ न्यूज

मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है। इस बार मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक सिपाही लोगों को परेशानियां दूर करने के लिए चर्च बुला रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हिन्दू संगठनों में आक्रोश का माहौल है। शुक्रवार को हिन्दू जागरण मंच के लोगों ने प्रेस वार्ता लेकर इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। यहीं संगठन के प्रतिनिधियों ने एसपी सिद्धार्थ तिवारी से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और सिपाही पर कार्रवाई की मांग की गई। एसपी ने मामले की जांच कराने और नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है।

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में शुक्रवार को हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष आकाश दुआ ने आरोप लगाया कि, पुलिस लाइन में पदस्थ सिपाही विमल तिर्की गांवों में धर्मांतरण करा रहा है। सिपाही अपने दो अन्य नाबालिग साथियों के साथ भलौर, चैनपुर, चनवारीडाड़ सहित आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डराकर धर्मांतरण के लिए उकसाता है। वह परेशानी दूर करने के नाम पर चैनपुर के चर्च में भी लोगों को बुलाता है। आकाश दुआ ने यह बताया कि सिपाही लोगों को मौत भी भय दिखाता है।

सोशल मीडिया में वायरल हुआ था वीडियो

जिलाध्यक्ष आकाश दुआ ने बताया कि इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इसकी शिकायत होने के बाद वीडियो को डिलीट करा दिया। प्रेसवार्ता के दौरान हिन्दू जागरन मंच के लोगों ने वीडियो भी दिखाया। इस दौरान मंच की ओर से कहा गया है कि अगर जल्द ही इसे लेकर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हिंदू संगठन आंदोलन करेंगे। इधर इस मामले में एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि वीडियो की जांच के बाद पुलिस की सर्विस कंडक्ट गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई होगी।

घर में घुसकर महिला को छेड़ा, आरोपी गिरफ्तार

धमतरी (ए)। महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सिहावा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक थाना सिहावा क्षेत्रातंर्गत प्रार्थिया महिला के घर में घुसकर हाथ, बांह पकड़कर छेड़छाड़ करने की प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना सिहावा में दिनांक 20.07.23 को अपराध क्रमांक 113/23 धारा 452, 354, 323 भादवि0 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर द्वारा महिलाओं पर घटित अपराध में त्वरित कार्यवाही करने का निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में एसडीओपी.नगरी मंयक रणसिंह के नेतृत्व में थाना प्रभारी सिहावा लेखराम ठाकुर द्वारा सिहावा पुलिस टीम भेजकर त्वरित कार्यवाही करते हुये टिकेश्वर जांगड़े पिता ईश्वर लाल जांगड़े उम्र 31 वर्ष साकिन हिन्छापुर सांकरा थाना सिहावा को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

भारी वाहन की चपेट में 20 से ज्यादा मवेशी 17 की मौत, हादसे के बाद चालक फरार

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। शहर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। यहां सड़क पर भारी वाहन की चपेट में आने से 17 मवेशियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है अज्ञात भारी वाहन के चालक ने लापरवाही पूर्वक 20 से ज्यादा मवेशियों को कुचल दिया और फरार हो गया। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार सिरगिट्टी थाना क्षेत्र धूमा सिलपहरी के पास हाईवे पर अज्ञात भारी वाहन ने 20 से ज्यादा मवेशियों को कुचल दिया। जिससे 17 मवेशियों की मौत हो गई। हादसा इतना विभत्स था कि देखने वाले भी विचलित हो गए मवेशियों के शव हाईवे पर इधर-उधर पड़े थे, चारों तरफ खून फैला था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से मवेशियों के शवों को सड़क से हटाया गया। वहीं पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक पर अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

इस हादसे को लेकर एक ओर अज्ञात वाहन चालक की लापरवाही सामने आ रही है वहीं पशुपालक भी इसके लिए जिम्मेदार है। मवेशियों को यूं खुला छोड़कर पशुपालक नियमों का उल्लंघन करते हैं। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी पशुपालकों द्वारा अपने मवेशियों को सड़क पर खुला छोड़ दिया जाता है। मवेशी सड़क पर इधर उधर बैठे रहते हैं जो कि दुर्घटनाओं को आंमत्रण देते हैं। हाल के दिनों में मवेशियों के कारण कई ऐसे हादसे हो चुके हैं।

खारून नदी में बह गए 16 मवेशी, नदी किनारे छोड़ा था चरवाहे ने, तीन के शव बरामद

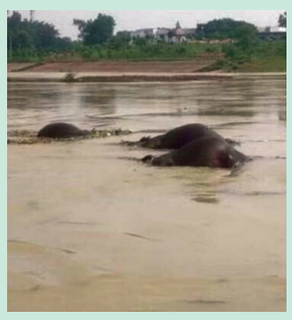

भिलाई। कुम्हारी थाना क्षेत्र स्थित खारुन नदी के तेज बहाव में 16 मवेशी बह गए। शुक्रवार को चरवाहे ने मवेशियों को नदी किनारे छोड़ दिया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान तेज बहाव में मवेशी बह गए। इस बीच मवेशी जलकुंभी में फंस गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से तीन मवेशियों के शव बरामद किए है। शेष मवेशियों को कुछ पता नहीं चला है।

बता दें छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश कारण इन दिनों खारुन नदी उफान पर है। शुक्रवार को चरवाहा अपनी मवेशियों को नदी किनारे छोड़कर गया था। इस दौरान मवेशी नदी की चपेट में आ गए और बह गए। आगे जाकर 12 से ज्यादा मवेशी जलकुंभी में फंस गए। जेसीबी से उन्हें निकालने का प्रयास शुरू किया गया, लेकिन तीन मवेशी ही मिले। उनकी भी मौत हो गई। बाकी नदी के बहाव में बह गए।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग बालोद संभाग बालोद
निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक-5310/NIT-9/2023-2024/ व ले लि दिनांक : 20/07/2023

निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :- 26/07/2023 अपरान्ह 5.30 बजे तक

ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदायें प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- 01/08/2023 अपरान्ह 5.30 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि :- 07/08/2023 पूर्वान्ह 11.30 बजे तक

एनआईटी क्र. निविदा	कार्य का नाम/ NoOfCalls	कार्य की अनुमानित लागत (लाख मे) अमानत राशि(रू.मे)
1	2	3
9 T0167	ग्राम खुन्दनी वि.ख. गुरुर के मुक्तिधाम से पुरानी बस्ती तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य ल.235 मीटर (भाग-अ) दिवतीय आमंत्रण	17.89 13418.00 268350.00
9 T0168	ग्राम कोचेरा वि.ख. गुरुर के दुर्गा मंदिर से आवासपारा तक सी.सी.मार्ग का निर्माण कार्य दिवतीय आमंत्रण	15.36 11520.00 230400.00
9 T0169	ग्राम कोचेरा वि.ख. गुरुर के दुर्गा मंदिर से आंगनबाड़ी तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य दिवतीय आमंत्रण	15.36 11520.00 230400.00
9 T0170	ग्राम खुन्दनी वि.ख.गुरुर के मुक्तिधाम से पुरानी बस्ती तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य ल.237 मीटर (भाग-ब)	18.03 13523.00 270450.00
9 T0171	ग्राम खुन्दनी वि.ख. गुरुर के मुक्तिधाम से पुरानी बस्ती तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य ल.233 मीटर (भाग-स)	17.74 13305.00 266100.00
9 T0172	ग्राम खुन्दनी वि.ख.गुरुर के दिना घर से मिडिल स्कूल तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य दिवतीय आमंत्रण	17.52 13140.00 262800.00
9 T0173	नर्मदा धाम ग्राम पंचायत सुरसुली में सी.सी. रोड निर्माण कार्य दिवतीय आमंत्रण	19.34 14505.00 290100.00
9 T0174	2023-24 लो नि वि अनुविभाग गुण्डरदेही के अंतर्गत शासकीय शहीद कौशल यादव महाविधालय गुण्डरदेही में सायकल स्टैण्ड का कार्य 20723 प्रथम आमंत्रण	18.66 13995.00 279900.00
9 T0175	2023-24 लो नि वि अनुविभाग गुण्डरदेही के अंतर्गत शासकीय शहीद कौशल यादव महाविधालय गुण्डरदेही में कैटीन निर्माण कार्य 20723 प्रथम आमंत्रण	12.37 9278.00 185550.00
9 T0176	2023-24 लो नि वि अनुविभाग कमांक १ बालोद केअंतर्गत टटेगा कसही गंधरी रानीतराई मार्ग लं 5.60 कि मी एवं नांहदा से खामतराई मार्ग लं 4.60 कि मी में विशेष मरम्मत का कार्य 20723 प्रथम आमंत्रण	15.83 11873.00 237450.00
9 T0177	2023-24 लो नि वि अनुविभाग कमांक १ बालोद के अंतर्गत राजनांदगांव अंतागढ मार्ग स्थित देवरी में आर सी सी डेन कव्हर एवं नाहंदा से राघोनवागांव मार्ग लं 4.00 कि मी में विशेष मरम्मत का कार्य	18.38 13785.00 275700.00

निविदा संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाईट www.pwd.cg.nic.in में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र मे उपलब्ध है। इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।

नियम व शर्तें :- 1) पंजीयन की छायाप्रति 2) पेन कार्ड की छायाप्रति 3) जी.एस.टी. प्रमाण पत्र की छायाप्रति 4) निविदाकारों की श्रेणी "द" से "अ" , निविदा प्रपत्र की कीमत राशि रू. 750.00 एवं कार्य की अवधि "02 माह " होगी। 5) निविदा प्रपत्र के साथ Annexure-1, Annexure-2 & Annexure-3 फार्म भरना अनिवार्य होगा नही भरे जाने पर आपका निविदा प्रपत्र निरस्त किया जावेगा। (प्रपत्र संलग्न)

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि.बालोद संभाग बालोद

जी-03552/5

सेक्टर-6 एंव रिसाली के प्रतिष्ठित संस्थान विज्ञापन के लिए संपर्क करें:- 9303289950, 9827806026, 8962815243

Galaxy Granite
WholeSaler & Retailer
रायपुर से कम दामों में
All Type Of Tiles : Wall Tiles, Floor Tiles, Granite Sanitary & Null Fitting
सभी प्रकार के टाईल्स और ग्रेनाईट मिलने का एक मात्र स्थान कोई भी टाईल्स लेने से पहले एक बार अवश्य पधारे...
Raja Steel Traders, Krishna Talkies, Road, Side of ZEE Maha Sale, Risali, Bhilai - 490006
K.K. Soni - 77479-88643, 9109509095

राकेश ट्रेडर्स
विगत 6 वर्षो से यह दुकान पानी टंकी के सामने स्थानांतरित हो गई है।
Dealers
Marbles, Grinight, Black Stone, Nano & Double Charge Verified Tiles Digital Wall & Floor Tiles Cement Coloru etc.
रायपुर रेट पर माल उपलब्ध
Rakesh Sahu
9302443750, 9907127357
Krishna Talkies Road, Beside Hariom Furniture, Risali, Bhilai - 490006

भिलाई मसाला उद्योग
शुद्ध कुटे हुए मसाले,पापड़, अचार, बड़ी, जड़ी-बूटी, जचकी का सामान इत्यादि
128, ए- मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई, फोन. 2284508, मो. 9826137766

House of tiles
Complete Range of Tiles, Marble And Granite in One Shop
KESWANI TILSE
कृष्णा टाकिज रोड, राजा स्टील के सामने, रिसाली, भिलाई (छ.ग.)
Mo. _- 82349 - 21000

भिलाई की सबसे बड़ी चुड़ी की दुकान
निखार बैंगल
मो.- 9826186026
Shop-47, 'A' Market, Sec-6, Bhilai Nagar, Distt., Durg (C.G.)

भारतीय बैग हाउस
फैंसी स्ट्राली, स्कूल बैग, ऑफिस बैग, सफर बैग, लेपटॉप बैग, फैंसी छतरी, रेनकोट इत्यादि के विक्रेता
VIP happy journey
AMERICAN TOURISTER
कृष्णा टाकीज रोड, बैंक ऑफ बडौदा के बाजू में रिसाली भिलाई, संजय गुप्ता : 93003-77572

खास - खबर

हाइटेंसन लाइन में खराबी के कारण कैम्प क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति प्रभावित

भिलाई। एचटी केबल की खराबी के कारण इस्पात नगरी के कैम्प एरिया क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बंद है। पावर हाउस रेलवे स्टेषन के नजदीक हाइटेंसन लाइन के निकट मरम्मत का कार्य जारी है। रेललाइन के नीचे से जाने वाली लाइन होने के कारण अनुरंक्षण कार्य में समय लग रहा है। भारी बारिष के कारण अनुरंक्षण कार्य में पर्याप्त गति न होने के कारण 21 जुलाई 2023 की रात को विद्युत आपूर्ति बाधित रहने की संभावना है। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएँ विभाग के अन्तर्गत टाउन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई है और आमजनता से सहयोग की अपेक्षा की है। टाउन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार कार्य प्रगति पर है और कल 22 जुलाई 2023 को संध्या तक विद्युत आपूर्ति सामान्य होने की संभावना है।

कर्बला के शहीदों की याद में लगाए पौधे, तकरीर जारी

भिलाई। मुहर्रम के मौके पर कर्बला के शहीदों की याद में अंजुमन हुसैनिया इमामबाड़ा जोन 1 सड़क 20, खुर्सीपार की ओर से 10 दिन तक विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को नमाजे जुमा के बाद आई टी आई रोड, जोन 1, खुर्सीपार में वृहद स्तर पर पौधरोपण किया गया। मुहर्रम पर यहां गुरुवार 20 जुलाई से तकरीर का सिलसिला शुरू हुआ है, जो अगले हफ्ते शुक्रवार 28 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान मुफ्ती मुकर्रिर खुसूसी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कलीमुल्लाह खान रिज़वी इलाहाबाद प्रयागराज तकरीर कर रहे हैं। अंजुमन कमेटी के सदर हुसैन अली अशरफी ने बताया कि इस साल पैगंबर हजरत मुहम्मद के वंशज आले नबी औलादे अली फर्जंद ए गौसे आजम हुजूर हजरत सैयद आलमगीर अशरफ अशरफी उल जिलानी भी 8 मोहर्रम बरोज गुरुवार 27 जुलाई को शिरकत करेंगे और महफिल से खिताब करेंगे। शुक्रवार को पौधारोपण के दौरान भिलाई पीयूष मिश्रा,(पार्षद), हुसैन अली अशरफी,अकबर अली, मुश्ताक अली, अरशद अय्यूब, मोहम्मद सगीर, हैदर अली, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद, तौहीद,पीर मोहम्मद, राज मोहम्मद, राशिद अहमद, आरिफ अयूब, मोहम्मद तुफैल, मोहम्मद साजिद और मो साहिल सहित अन्य लोग मौजूद थे।

रामनगर सुपेला में कल होगी पावस काव्य संध्या

भिलाई। साहित्य सृजन परिषद द्वारा 23 जुलाई रविवार को अपराह्न 3-30 बजे से पावस काव्य संध्या गोष्ठी का आयोजन इंदिरा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल रामनगर सुपेला में किया गया है। मुख्य अतिथि आचार्य डॉ महेश चंद्र शर्मा होंगे। अध्यक्षता साहित्य सृजन परिषद के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कवि एन.एल.मौर्य 'प्रीतम' करेंगे। बौद्ध साहित्य विद रवीन्द्र गाड़गे एवं कवयित्री श्रीमती प्रीति सरू ' गुन गुन ' विशिष्ट अतिथि होंगे। समिति के उपाध्यक्ष राम बरन कोरी ' कशिश ' स्वागत भाषण देंगे। उपाध्यक्ष नीता कम्बोज ' शीरी ' का संचालन और उपाध्यक्षा नीलम जायसवाल का आभार ज्ञापन होगा। क्षेत्र के जाने-माने और अपनी - अपनी साहित्यिक शैली में माहिर कवि गण इस काव्य सन्ध्या में रोचक काव्य पाठ करेंगे। परिषद अध्यक्ष ' प्रीतम ' ने साहित्य रसिकों से इस काव्य गोष्ठी में गरिमामय उपस्थिति का अनुरोध किया है।

प्रबंधन का स्पष्ट निर्देश लीज शर्तों का ना करे उल्लंघन

लीज रजिस्ट्री पर बीएसपी की एंट्री लीजधारकों को मालिकाना हक नही

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। बीएसपी टाउनशिप में लीजधारको द्वारा लीज डीड की रजिस्ट्री व इसे लेकर सामने आ रही अफवाहों के बाद भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन स्पष्टीकरण जारी किया है। प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि लीज डीड रजिस्ट्री केवल न्यायालय के समक्ष साक्ष्य मात्र है। लीजधारी इसे मालिकाना हक न समझे। लीजधारक किसी भी तरह के भ्रामक प्रचार में न रहें और नियम व शर्तों का उल्लंघन करने से बचे।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भिलाई स्टील प्लांट, सेल-बीएसपी के संज्ञान में आया है कि, सोशल मीडिया में कुछ संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं और कुछ समाचार पत्रों में समाचार लेख प्रकाशित किए गए हैं, जिनसे भिलाई टाउनशिप, जिला दुर्ग स्थित सेल बीएसपी के लीजधारकों एवं अन्य लीजधारकों के मन में संदेह और भ्रम पैदा हो सकता है।

लीजधारकों के हित में यह जानकारी प्रदान की जा रही है। इसलिए लीजधारकों के बीच इस तरह के संदेशों से प्रभावित ना होने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लीज के पंजीकरण के परिणामों के बारे में कानूनी स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है कानूनी तौर पर 'लीज', लीजधारक और लीज देने वाले (लीजदाता) के बीच सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार, जब तक लीजधारक लीज के अनुबंधों का पालन करता है, तब तक केवल संपत्ति का उपभोग करने के अधिकार का हस्तांतरण है। यह लीजधारक के पक्ष में कोई स्वामित्व नहीं बनाता है। इसलिए लीजधारक और लीज देने वाले (इस प्रकरण में सेल बीएसपी) के बीच संबंध सेल के नियमों और शर्तों पर मकान को लीज पर देने की योजना, आबंटन आदेश और लीज समझौते के अनुसार शासित होते रहेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि, लीजधारक द्वारा अनुबंध का उल्लंघन करने पर लीज निर्धारित या समाप्त करने का लीजदाता अर्थात सेल बी.एस.पी का अधिकार किसी भी प्राधिकारी द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। पंजीकृत लीज डीड न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में है। इसलिए यह लीजधारक के हित में है कि, वह लीज की शर्तों का उल्लंघन ना करे। इसलिए सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि, पंजीकृत किए जा रहे लीज डीड की शर्तें विशेष रूप से लीजदाता यानि सेल-बीएसपी द्वारा समाप्त करने की शक्ति निर्धारित करती है। लीज की शर्तों के उल्लंघन में तीसरे पक्ष या किसी भी प्राधिकारी द्वारा की गई किसी भी कानूनी कार्रवाई का बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा और लीज को निर्धारित /समाप्त करने के लिए लीजदाता अर्थात सेल बीएसपी की शक्ति में कटौती नहीं होगी। लीज समझौते के कानूनी संदर्भ में किसी के द्वारा लीजधारक को दिया गया कोई भी आश्वासन, नियमितीकरण या अन्य, जो लीज की शर्तों का उल्लंघन करता है, से लीज की शर्तों के तहत लीजदाता के रूप में सेल बीएसपी के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए लीजधारकों को उनके हित में उपरोक्त के बारे में सूचित एवं सजग किया जा रहा है। सभी के संज्ञान में लाना उचित है कि, टाउनशिप में सेल बीएसपी के स्वामित्व वाली संपत्ति सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 के तहत सार्वजनिक परिसर है और भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन द्वारा आबंटन और लीज की शर्तों के अनुसार आबंटित, प्रबंधित और संचालित की जाती है। इसलिए लीज भी पीपी एक्ट 1971 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। लीजधारकों की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि, लीजधारक या आबंटी द्वारा आबंटित सार्वजनिक परिसर में कोई भी अनाधिकृत निर्माण की अनुमति नहीं है और यह आबंटन की शर्तों का उल्लंघन है। किसी भी अनाधिकृत निर्माण सहित आबंटन/लीज की शर्तों का उल्लंघन होने पर आबंटन रद्द किया जा सकता है और ऐसे आबंटियों या लीजधारकों के विरुद्ध पूर्व में भी कार्रवाई की गई है और वर्तमान में भी की जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह फिर से स्पष्ट किया जाता है और दोहराया जाता है कि, आबंटन/लीज के नियमों और शर्तों के अनुसार आबंटी/लीजधारक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इसलिए सेल-बीएसपी की सहमति के बिना किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश सेल-बीएसपी पर बाध्यकारी नहीं है।

इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दे लीजधारी

1. बीएसपी की सहमति के बिना लीजधारक नियमितीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।
2. लीज,लाइसेंस,आबंटन के नियमों के अनुसार सेल-बीएसपी ऐसे सभी आबंटियो, लायसेंसियों , लीजधारकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।
3. प्रबंधन की सहमति के बिना किया गया कोई भी नियमितीकरण आबंटी,लीजधारक के जोखिम और लागत पर होगा।
4. आबंटित के द्वारा किया गया कोई भी नियमितीकरण कार्य सेल-बीएसपी पर बाध्यकारी नहीं है।
5. किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक से ऋण प्राप्त करने के संदर्भ में लीजधारक को लीजदाता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना चाहिए।
6. प्रचारित किए जा रहे संदेशों एवं नए रिपोर्टों से गुमराह ना हों, जो कि, उपर्युक्त के विपरीत हैं। यह लीजधारकों के हित में जारी किया गया है।

महापौर नीरज पाल ने बनवाया अपना आयुष्मान कार्ड

भिलाई निगम की अपील हर व्यक्ति बना ले अपना आयुष्मान कार्ड और ले स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, निगम का अमला डोर टू डोर घरों में जाकर हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में महापौर नीरज पाल ने भी शिविर में आयुष्मान कार्ड बनाने पंजीयन करवाये थे और आज उनका आयुष्मान कार्ड बनकर आया। निगम का अमला जिनका राशन कार्ड एवं आधार कार्ड बना हुआ है उनका आयुष्मान कार्ड तत्काल स्पॉट पर ही बनाने का प्रोसेस किया जा रहा है।

जिनके पास राशन कार्ड एवं आधार कार्ड नहीं है वह भिलाई नगर निगम के गुरुद्वारा द्वारा स्थित नेहरू नगर के जोन कार्यालय, वैशाली नगर पानी टंकी स्थित जोन कार्यालय, मदर टेरेसा नगर चंद्रा मौर्या स्थित जोन कार्यालय, खुर्सीपार डबरा पारा स्थित जोन कार्यालय तथा सेक्टर 6 आत्मानंद स्कूल परिसर में स्थित जोन कार्यालय में संपर्क करके आधार अपडेशन व राशन कार्ड बनवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए निगम के मुख्य कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है। यहां यह बताना आवश्यक होगा कि 10 वर्ष पूर्व जिन्होंने आधार कार्ड बनवाया हैं उन्हें अपना आधार कार्ड अपडेशन करवाना अत्यंत अनिवार्य है। निगम प्रशासन की अपील है कि एपीएल एवं बीपीएल राशन कार्ड धारी जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है वह शीघ्र ही अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लें। डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत एपीएल कार्ड धारी को प्रति व्यक्ति 50,000 तथा बीपीएल राशन कार्ड धारी परिवारों को प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 500000 की स्वास्थ्य सहायता का प्रावधान निहित है, जिसका लाभ आयुष्मान कार्ड धारी को ही मिलेगा। मैनेजर अमन पटले ने जानकारी देते हुए बताया कि भिलाई निगम के द्वारा बीते एक माह में 16000 हजार तथा 26 अप्रैल से अब तक लगे शिविर में 53000 हजार नागरिकों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है तथा छूटे हुए लोगों से डोर टू डोर संपर्क करके उनका आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया जा रहा रहा है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर भिलाई निगम क्षेत्र हर नागरिक का आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। परिवार का हर सदस्य आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है और स्वास्थ्य योजना का लाभ उठा सकता है। निगम की अपील है कि डोर टू डोर जा रही महिलाओं को सहयोग प्रदान करते हुए अपना आयुष्मान कार्ड शीघ्रता से बनवा ले।

विकास कार्यों के लिए 70 लाख 47 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा विधानसभा क्षेत्र भिलाई में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत विधायक देवेन्द्र यादव की अनुशंसा पर 18 निर्माण कार्यो के लिए 70 लाख 47 हजार 699 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र भिलाई के वार्ड क्रमांक 39 चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित निखिल रेसिडेंसी के पीछे शिव मंदिर के समीप वाटर एटीएम स्थापना हेतु 2 लाख 99 हजार, वार्ड क्र. 40 मंगल बाजार परिसर में प्रकाश व्यवस्था हेतु 6 लाख 99 हजार, वार्ड क्रमांक 42 मरियम्मा मंदिर के समीप डोम शेड निर्माण कार्य हेतु 2 लाख 99 हजार, वार्ड क्र. 43 शास. पू.मा. शाला बापूनगर खुर्सीपार में 1 नग बोर खनन कार्य हेतु 1 लाख, वार्ड क्र. 44 लक्ष्मीनारायण वार्ड में सार्वजनिक मंच निर्माण हेतु 5 लाख, वार्ड क्र. 45 बेन्थो उड़िया भवन के समीप सार्वजनिक मंच निर्माण हेतु 3 लाख, वार्ड क्रमांक 46 सामुदायिक भवन में जिम सामग्री प्रदाय हेतु 6 लाख, वार्ड क्र. 47 न्यू खुर्सीपार मशाल चौक के पास शेड निर्माण हेतु 4 लाख 99 हजार, वार्ड क्र. 47 पीपल पेड़ के पास मंच निर्माण हेतु 4 लाख, वार्ड क्रमांक 48 शिव मंदिर के समीप शौचालय निर्माण हेतु 2 लाख, वार्ड क्र. 49 सुभाष मार्केट स्थित सार्वजनिक फ्रेंड्स क्लब में मल्टीपल जिम सामग्री प्रदाय हेतु 4 लाख, वार्ड क्र. 49 में वाटर कूलर लगाने हेतु 1 लाख 49 हजार, वार्ड क्र. 49 काली मंदिर के पास सार्वजनिक मंच निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु 3 लाख 99 हजार, वार्ड क्र. 51 श. वीर नारायण सिंह नगर स्थित तेल्हा नाला के पास सार्वजनिक मंच निर्माण हेतु 3 लाख, वार्ड क्र. 51 शहीद वीर नारायण सिंह नगर स्थित बमलेश्वरी मंदिर के पास मंच निर्माण हेतु 5 लाख एवं एचएससीएल कॉलोनी खुर्सीपार में सार्वजनिक भवन निर्माण कार्य हेतु 4 लाख 99 हजार रुपए के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति की गई है।

बारिश के चलते भिलाई निगम अलर्ट, पानी निकासी के लिए जुटी रही निगम की टीम

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत बारिश के पानी से कहीं भी जलभराव की स्थिति न हो इसके लिए महापौर नीरज पाल के निर्देश पर निगम के अधिकारी व निगम का स्वास्थ्य अमला जुटा हुआ है। महापौर नीरज पाल और निगमायुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर निगम के जोन आयुक्त व अधिकारी, स्वास्थ्य टीम के साथ बस्तियों में अवलोकन करने पहुंचे और समक्ष नालियों को साफ करवाया।

सभी वार्डों के छोटे, बड़े नाली की सफाई की जा रही है ताकि पानी की निकासी बिना कोई अवरोध गंतव्य की ओर निकल सके साथ ही जहां निकासी की व्यवस्था नहीं है वहां वैकल्पिक व्यवस्था करने

निकासी की व्यवस्था बनाई जा रही है। निगम के सफाई कर्मी वार्डों के भीतर नाली से पानी निकासी करने झिल्ली, पन्नी व कचरे को निकालने में जुटे रहे। बारिश की वजह से कहीं भी जलभराव की स्थिति निर्मित न हो इसके लिए निगम की टीम मौके पर पहुंच रही है। गौरतलब है कि निगम मेयर व आयुक्त के निर्देश पर निगम प्रशासन ने बारिश पूर्व ही सभी नाली व बड़े नालों की जेसीबी से सफाई कराई थी, जिसके कारण जलभराव की शिकायतें नगण्य आ रही है। भिलाई निगम क्षेत्र में बारिश का पानी सुगमता से तालाब व बड़े नालो तक बिना अवरोध पहुंच सके इसलिए नाले व वार्डों के भीतर जल निकासी वाले सभी नालियों की सफाई पूर्व में ही कराई जा चुकी है। बारिश के पानी से जलभराव की स्थिति से निपटने कुछ स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी वार्डों के भीतर जलभराव होने वाले स्थान पर कच्चा रास्ता बनाकर पानी को निकालने में जुटे रहे। कई स्थानों पर जाम नाली से झिल्ली, पन्नी एवं अन्य कचरो को निकालकर साफ किया गया। बारिश के पानी को निकालने सफाई कर्मियों ने वार्डो के भीतर फावड़ा, बेलचा व अन्य औजार के साथ वार्ड के नाली का निरीक्षण किए और जलजमाव वाले स्थानों से पानी की निकासी हेतु रास्ता बनाकर निकाला। नाली से जलप्रवाह को बनाए रखने सभी जोन के जोन स्वास्थ्य अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में निरीक्षण किए और कई स्थानों पर जलनिकासी के लिए रास्ता बनवाया। आज कैलाश नगर भगवा चौक के पास जवाहर नगर एवं साकेत नगर आदि इलाकों में पानी निकासी की व्यवस्था बनाई गई।

टाउनशिप का पानी निकालने बरसते पानी में कवायद

तालपुरी में गलत डिजाइन बना जलभराव का कारण, दो घंटे बाद स्थिति सामान्य

श्रीकंचनपथ न्यूज

रिसाली। तेज बारिश के दौरान निचली बस्ती और पॉश कालोनी में निर्मित स्थिति से निपटने जनप्रतिनिधि और निगम आयुक्त की टीम एकजुटता दिखाई। जल भराव की स्थिति से जल्द निजात दिलाने फावड़ा और लोहे के एंगल से श्रमिकों का हाथ बटाया। तालपुरी में गलत डिजाइन की वजह से ढलान क्षेत्र में बने परिजात में पानी भरने लगा था। जिसे निकालने वृहद रूप से राहत कार्य चलाया गया। स्थिति सामान्य होने के बाद ही अधिकारियों ने राहत की सांस ली।

शुक्रवार की अलसुबह शुरू हुई तेज बारिश से जल भराव की स्थिति विकराल होने से पहले ही रिसाली निगम अमला बिना देरी किए मोर्चा सम्भाला। निचली बस्ती और ढलान में बसे कालोनी में एकत्र हुए पानी को निकाला गया।जलभराव से लोगों को निजात दिलाने महापौर शशि सिन्हा, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री जितेन्द्र साहू राहत कार्य में हाथ बढ़ाया। आयुक्त आशीष देवांगन के मार्गदर्शन में पानी निकासी का संसाधन बनाने 4 घंटे से भी अधिक समय लगा।

निगम अमला पहले वार्ड 28 शक्ति विहार रिसाली क्षेत्र पहुंचा। इसके बाद इंटरनेशनल कालोनी तालपुरी। इस दौरान वार्ड पार्षद डॉ. सीमा साहू, जोन अध्यक्ष अमृतपाल सिंह, अशोक सिन्हा, अमनदीप सोढ़ी, प्रेम साहू आदि उपस्थित थे।

टाउनशिप का पानी ले रहा था बाढ़ का शक्ल

सांई मंदिर के सामने व वीआईपी नगर पहुंच मार्ग के सामने जल भराव की स्थिति बनी। दरअसल यहां पर रिसाली सेक्टर (टाउनशिप) का पानी जमा होने लगा था। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो इसके पहले निगम ने जमा पानी निकासी के लिए वीआईपी नाला तक रास्ता तैयार किया।

शक्ति विहार के लोगों को राहत

तेज बारिश से इस बार शक्ति विहार में रहने वाले नागरिकों ने राहत की सांस ली। जलभराव से निजात दिलाने निगम आयुक्त ने मुख्य नाला में लगे हयुम पाइप की जगह कलवट निर्माण कराया है। नाला चैड़ीकरण कर नाला में पानी का फ्लो अधिक होने पर ओवर फ्लो पानी निकासी के लिए अलग संसाधन तैयार कराया गया गया है।

घुटने तक भरा था पानी

तालपुरी बी ब्लाक पारिजात में तीन फीट तक पानी भरा हुआ था। ब्लाक 40 से 60 पहुंच मार्ग बाधित हो गया था। सूचना मिलते ही आयुक्त जनप्रतिनिधियों के साथ तालपुरी पहुंचे और निरीक्षण किया। दरअसल यहां पर कालोनी निर्माण के समय तैयार गलत डिजाइन को नजरअंदाज करने से स्थिति बिगड़ी। अधिकारी व कर्मचारी पहले घुटने तक भरे पानी को कालोनी से बाहर निकालने संसाधन तैयार किया। इसके बाद पानी निकासी में रोड़ा बने डिजाइन को जेसीबी से हटाया।

कलेक्टर ने फिर किया आयुक्त के साथ शहर में निरीक्षण

शहर के प्रमुख मार्गो के किनारे फुटपाथों पर लगें अवैध कब्जे को हटाने के निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत आज फिर शाम को कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के साथ शहर निरीक्षण करने निकले,उन्होंने सबसे पहले जीवन प्लाजा पहुंचे। जिसके सामने अनियंत्रित पार्किंग हो रही है, जिससे यातायात बाधित होता है उन्होंने जीवन प्लाजा के मालिक को पार्किंग स्थान (बेसमेंट) में पार्किंग कराने हेतु नोटिस दिये जाने एवं जुर्माना आरोपित करने को कहा। इसके लिए जीवन प्लाजा के मालिक को व्यवस्थित पार्किंग करने और अपने कर्मचारी तैनात किये जाने के लिए मालिक से चर्चा कर कार्रवाही करन कहा।इसके अलावा जीवन प्लाजा के बाजू रोड में गंदगी होना पाया गया जिसकी साफ-सफाई करवाने के लिए कहा गया।गंज काम्प्लेक्स नव निर्माणधीन सी मार्ट के सामने मालवाहक वाहनों की पार्किंग हो रही है जिसे हटाने के लिए कार्यवाही करने के लिए यूनियन के पधाधिकारियों से संपर्क कर वैकल्पिक स्थल के चयन हेतु

प्रस्ताव प्रस्तुत करने निर्देश दिए। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के साथ निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से कहा कि कलेक्ट्रेट के सामने अव्यवस्थित ठेला गुमटी वालों को हटाकर व्यवस्थित करने के संबंध में कार्यवाही करें।लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सामने अतिक्रमण कर दुकाने संचालित है, हटाकर वेंडिंग जोन बनाया जाये तथा बस स्टैण्ड के सामने स्थित ठेला गुमटी को वहां से हटाएं। यातायात बाधित हो रहा है। जिला उद्योग केन्द्र के सामने स्थित अतिक्रमण एवं अवैध पार्किंग को सोमवार तक हटाया जावे एवं व्यापारियों को नोटिस जारी कर जुर्माने की कार्यवाही करने की बात कही।कलेक्टर ने जिला उद्योग केंद्र के पास पहुँचे उन्होंने जिला उद्योग केन्द्र के सामने निर्मित मुख्यमंत्री स्वावलंबन की दुकानों के व्यापारियों द्वारा सड़क पर वाहन एवं सामान एकत्रित किये गये हैं उन्हें सोमवार तक रोड को रिक्त कर अपनी दुकान के सामने रोड के पीछे सामान व्यवस्थित रखने हेतु सोमवार तक कार्यवाही के लिए अधिकारियों से कहा। कहा कि अगले भ्रमण में स्थल को पुन: निरीक्षण कर जायजा लिया जाएगा।उन्होंने कब्रवाल पेट्रोल पंप के आगे एवं साइंस कालेज नहर किनारे रिक्त स्थल पर वेंडिंग जोन बनाने एवं रोड के अव्यवस्थित फुटकर व्यापारियों को व्यवस्थापन किये जाने के लिए कहा।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950